www.railsamacharbureauald.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

# रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

"आपदा हो या उत्सव का समय, भारतीय रेल हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ी रहती है। संकट की घड़ी में यही सबसे मजबूत सहारा बनकर उभरती है।"

"एक सदी से अधिक की विरासत और आधुनिक तकनीक के संगम के साथ भारतीय रेल परंपरा और परिवर्तन का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करती है।"

वर्ष-36 अंक:04 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 16-28 फरवरी 2026 पृष्ठ 12, (सयुक्तांक) मूल्य:20 रु. मात्र, डाक खर्च (रंगीन सहित)

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से यात्रा का समय कम होगा। दिल्ली-वाराणसी की यात्रा 3 घंटे 50 मिनट में, वाराणसी-सिलीगुड़ी की यात्रा 2 घंटे 55 मिनट में, चेन्नई-बेंगलुरु की यात्रा 1 घंटे 13 मिनट में और मुंबई-पुणे की यात्रा 48 मिनट में पूरी होगी

## यात्री-केंद्रित रेलवे आधुनिकीकरण, बढ़ी सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास को नई गति

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत देश भर में रेल विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिला है, जिसमें राज्यों को कनेक्टिविटी को मजबूत करने, यात्री सुरक्षा बढ़ाने, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने और माल ढुलाई नेटवर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। यह निरंतर निवेश सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो रेलवे को देश भर में आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स दक्षता के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करता है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में, रेल मंत्रालय ने रेल निवेश को क्षेत्रीय एकीकरण, यात्री सुविधा और राज्यों में आर्थिक अवसरों के चालक के रूप में मजबूती से स्थापित किया है, जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी, मल्टी-मॉडल गतिशीलता, विद्युतीकरण और सुरक्षित लॉजिस्टिक्स जैसी प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्य में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के माध्यम से बडा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इनका उद्देश्य प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच यात्रा के समय को काफी कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और मार्ग में पड़ने वाले द्वितीय श्रेणी के शहरों को जोड़ना है। प्रस्तावित वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण धार्मिक, शैक्षणिक और चिकित्सा केंद्रों को जोड़ेगा। दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड कॉरिडोर से लगभग 3 घंटे 50 मिनट में यात्रा संभव हो सकेगी। इसके अलावा, वाराणसी से पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच लगभग 2 घंटे 55 मिनट में यात्रा संभव हो सकेगी। पश्चिम बंगाल को भी पूर्वी भारत में सिलीगुड़ी से वाराणसी को जोड़ने वाली पहली हाई-स्पीड रेल सेवा से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे अंतर-क्षेत्रीय आवागमन में सुधार होगा और व्यापार एवं सेवा के अवसर बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर और आसपास के क्षेत्रों में रिकॉर्ड आवंटन से नई रेल लाइनों का निर्माण, स्टेशनों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा में सुधार हुआ है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और देश के बाकी हिस्सों से संपर्क मजबूत हुए हैं।

एक प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला 40 किलोमीटर लंबा भूमिगत रेल गलियारा है। भूमिगत रेल पटरियां बिछाने और मौजूदा पटरियों को चार-लाइन की बनाने की योजना चल रही है, जिससे अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा और यात्रियों तथा माल ढुलाई दोनों के लिए इस महत्वपूर्ण पारगमन क्षेत्र में निर्बाध और सुगम रेल आवागमन सुनिश्चित होगा।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों का उन्नयन कर रहे हैं, जिससे रेल सुरक्षा, स्थिरता और यात्री सुविधाओं में सुधार हो रहा है। दक्षिण भारत में, राज्यवार रेलवे आवंटन स्पष्ट रूप से उच्च-प्रभाव वाली यात्री कनेक्टिविटी की ओर लक्षित हैं, जो हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और आसपास के शहरी केंद्रों को जोड़ने वाले उभरते हाई-स्पीड रेल ''डायमंड'' नेटवर्क पर आधारित है। यह नेटवर्क दक्षिण भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा, जिससे आईटी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निर्बाध आवागमन संभव होगा। भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में बेंगलुरु को सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि यह व्यावसायिक यात्रा, प्रतिभा आवागमन और अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए कहीं अधिक सुलभ हो जाएगा।

हाई-स्पीड कॉरिडोर के पूरा होने के बाद, चेन्नई-बेंगलुरु की यात्रा में लगभग 1 घंटा 13 मिनट, बेंगलुरु-हैदराबाद की यात्रा में लगभग 2 घंटे और चेन्नई-हैदराबाद की यात्रा में लगभग 2 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। महाराष्ट्र में, आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा उच्च प्रभाव वाली, क्षमता-बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर केंद्रित है, विशेष रूप से मुंबई-पुणे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, भीड़भाड़ वाले मुख्य मार्गों का विस्तार, प्रमुख स्टेशनों का आधुनिकीकरण और पुनर्विकास और राज्य की तेजी से बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करने के लिए उपनगरीय और अंतर-शहरी रेल सेवाओं को मजबूत करना।

पश्चिमी और मध्य भारत में, आगामी मुंबई-पुणे हाई-स्पीड कॉरिडोर से यात्रा का समय घटकर लगभग 48 मिनट हो जाएगा, जिससे दो प्रमुख शहरी केंद्र प्रभावी रूप से जुड़ जाएंगे। पुणे से हैदराबाद तक लगभग 1 घंटे 55 मिनट में कनेक्टिविटी और आगे दक्षिणी केंद्रों तक कनेक्टिविटी से क्षेत्रों में एक निरंतर हाई-स्पीड नेटवर्क बनेगा, जिससे यात्रियों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं दोनों को लाभ होगा।

हिमालयी और उत्तरी क्षेत्रों में, बजट में आर्थिक पहुंच, पर्यटन और हर मौसम में सुगम आवागमन को बढ़ावा देने का प्रावधान है। उत्तराखंड की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग लाइन, जिसमें जटिल सुरंगें होंगी, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार करेगी, यात्रा का समय कम करेगी और विद्युतीकरण तथा सुरक्षा उन्नयन में व्यापक निवेश के साथ-साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आवागमन को सुगम बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में नेटवर्क विस्तार, आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। जम्मू-कश्मीर में, उडी की ओर विस्तार सहित मजबूत रेल संपर्क, सर्दियों में होने वाली बाधाओं के बावजूद साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, जिससे यात्रियों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

झारखंड, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाले डंकुनी (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक पूर्व-पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे के माध्यम से माल ढुलाई क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। यात्रियों के लिए, इन पहलों का अर्थ है कम यात्रा समय, सुरक्षित और अधिक आरामदायक रेलगाडियां, आधुनिक स्टेशन, भीड़भाड़ में कमी और बेहतर अंतिम-मील कनेक्टिविटी। साथ ही, समर्पित माल ढुलाई गलियारों, आधुनिक इंजनों, उन्नत पटरियों और उन्नत सिग्नलिंग के माध्यम से भारतीय रेलवे के 3,000 मिलियन टन माल ढुलाई के दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, जिससे यात्री सेवाओं को बाधित किए बिना माल की आवाजाही तेज हो सकेगी।

## राज्यवार रेल बजट आवंटन विवरण

**आंध्र प्रदेश:** आंध्र प्रदेश में रेलवे अवसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। राज्य और तेलंगाना के लिए वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 886 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 10,134 करोड़ रुपये हो गया है, जो ग्यारह गुना वृद्धि दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण निवेश से 92,649 करोड़ रुपये की चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र:** असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे का उल्लेखनीय विकास हुआ है। वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 2,122 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 11,486 करोड़ रुपये हो गया है, जो पांच गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है। इस निधि से 72,468 करोड़ रुपये की चल रही परियोजनाओं को सुगम बनाया गया है।

**बिहार:** बिहार में रेलवे अवसंरचना में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 1,132 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 10,379 करोड़ रुपये हो गया है, जो नौ गुना वृद्धि है। इस अभूतपूर्व निवेश से 1,09,158 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**छत्तीसगढ़:** छत्तीसगढ़ में रेलवे अवसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 311 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7,470 करोड़ रुपये हो गया है, जो 24 गुना वृद्धि है। इस महत्वपूर्ण निवेश से 51, 080 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**दिल्ली:** दिल्ली में रेलवे अवसंरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 2,711करोड़ रुपये हो गया है, जो 28 गुना वृद्धि है। इस निवेश से 8,976 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चल रही परियोजनाओं को सुगम बनाने में सहायता मिली है।

**गोआ:** गोआ के रेलवे अवसंरचना को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, 2026-27 में 515 करोड़ रुपये के आवंटन से 4,344 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**गुजरात:** गुजरात के रेलवे अवसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, वार्षिक औसत बजट 2009-14 के दौरान 589 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 17,366 करोड़ रुपये हो गया है, जो 29 गुना वृद्धि है। इस ऐतिहासिक निवेश से 1,28,748 करोड़ रुपये के चल रहे कार्यों को संभव बनाया गया है।

**हरियाणा:** हरियाणा में रेलवे अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, वार्षिक औसत बजट 2009-14 के 315 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 3,566 करोड़ रुपये हो गया है, जो 11 गुना वृद्धि है। इस ऐतिहासिक निवेश से 12,091 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**हिमाचल प्रदेश:** हिमाचल प्रदेश में रेलवे अवसंरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 108 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपये हो गया है, जो 27 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस निवेश से 17,711 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**जम्मू-कश्मीर:** जम्मू-कश्मीर में रेलवे अवसंरचना में निरंतर विकास हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 1,044 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,086 करोड़ रुपये हो गया है। इस निवेश से 522 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**झारखंड:** झारखंड में रेलवे अवसंरचना में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 457 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7,536 करोड़ रुपये हो गया है, जो 16 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस ऐतिहासिक निवेश से 63,470 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**कर्नाटक:** कर्नाटक में रेलवे अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 835 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7,748 करोड़ रुपये हो गया है, जो नौ गुना वृद्धि है। इस निवेश से 52,950 करोड़ रुपये की लागत वाली चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**केरल:** केरल में रेलवे अवसंरचना में निवेश और विकास में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जहां राज्य के वार्षिक औसत रेलवे बजट आवंटन में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है, जो 2009-14 में 372 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 3,795 करोड़ रुपये हो गया है। इस ऐतिहासिक अनुदान वृद्धि से 18,041 करोड़ रुपये की लागत वाले चल रहे कार्यों को समर्थन मिला है।

**मध्य प्रदेश:** मध्य प्रदेश में रेलवे निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 632 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 15,188 करोड़ रुपये हो गया है, जो 24 गुना वृद्धि है। इस ऐतिहासिक आवंटन से कुल 1,18,379 करोड़ रुपये की चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**महाराष्ट्र:** महाराष्ट्र में रेलवे अवसंरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 1,171 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 23,926 करोड़ रुपये हो गया है, जो 20 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस अभूतपूर्व निवेश से 1,70,058 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**ओडिशा:** ओडिशा में रेलवे अवसंरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 838 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 10,928 करोड़ रुपये हो गया है, जो 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस ऐतिहासिक निवेश से 90,659 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**पंजाब:** पंजाब में रेलवे अवसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 225 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 5,673 करोड़ रुपये हो गया है, जो 25 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस ऐतिहासिक निवेश से कुल 26,382 करोड़ रुपये की लागत वाली चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**राजस्थान:** राजस्थान में रेलवे अवसंरचना में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 682 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 10,228 करोड़ रुपये हो गया है, जो 15 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस ऐतिहासिक निवेश से 56,863 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**तमिलनाडु:** तमिलनाडु में रेलवे अवसंरचना में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 879 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7,611 करोड़ रुपये हो गया है, जो नौ गुना वृद्धि दर्शाता है। इस महत्वपूर्ण निवेश से 35,701 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**तेलंगाना:** तेलंगाना में रेलवे अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 886 करोड़ रुपये (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) से बढ़कर 2026-27 में 5,454 करोड़ रुपये हो गया है, जो छह गुना वृद्धि दर्शाता है। इस बड़े निवेश से कुल 47,984 करोड़ रुपये की चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**उत्तर प्रदेश:** उत्तर प्रदेश में रेलवे अवसंरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 1,109 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 20,012 करोड़ रुपये हो गया है, जो 18 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस विशाल निवेश से 92,056 करोड़ रुपये की लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**उत्तराखंड:** उत्तराखंड में रेलवे अवसंरचना में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 187 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 4,769 करोड़ रुपये हो गया है, जो 26 गुना वृद्धि दर्शाता है। इस निवेश से 39,491 करोड़ रुपये की लागत वाली चालू परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

**पश्चिम बंगाल:** पश्चिम बंगाल में रेलवे अवसंरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जहां वार्षिक औसत बजट 2009-14 में 4,380 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 14,205 करोड़ रुपये हो गया है, जो तीन गुना वृद्धि दर्शाता है। इस ऐतिहासिक निवेश से कुल 92,974 करोड़ रुपये की चल रही परियोजनाओं को समर्थन मिला है।

# 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का निर्माण करने की योजना: अश्विनी वैष्णव

सूत्र/रे.स.ब्यू- सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वंदे स्लीपर जैसे नए रेल गाड़ियों के विकास की प्रक्रिया में एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें तकनीकी नवाचार, रणनीतिक योजना और उत्पादन का समन्वय होता है, ताकि सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके। इसमें प्रोटोटाइप का विकास, व्यापक परीक्षण शामिल होते हैं, जिसके बाद श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन निर्माण कार्यक्रम को बीईएमएल और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई और तकनीकी साझेदारों द्वारा प्रोटोटाइप विकास, परीक्षण और श्रृंखला उत्पादन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।

इन ट्रेनसेट को नियमित यात्री सेवा में शामिल करने का काम मांग और परिचालन तत्परता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट्स के कुल 260 रैक का निर्माण करने की योजना बनाई गई है।

यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने और सुरक्षित व आरामदायक यात्रा के मामले में नए मानक स्थापित करने के लिए, इन ट्रेन सेटों को आधुनिक कोच के साथ प्रदान किया गया है, जिनमें उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ और यात्री सुविधाएँ शामिल हैं ।

- झटका-रहित अर्ध-स्थायी कनेक्टर और एंटी क्लाइंबर
- कवच से लैस
- 180/160 किमी प्रति घंटे के डिजाइन/संचालन गति के साथ उच्च त्वरण
- ई एन मानकों के अनुरूप कार बॉडी का क्रैश-योग्य डिजाइन
- अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रत्येक कोच के अंत में फायर बैरियर दरवाजे,
- बेहतर अग्नि सुरक्षा विद्युत कैबिनेट और शौचालय में एरोसोल आधारित अग्नि पहचान और रोकथाम प्रणाली
- ऊर्जा दक्षता के लिए पुनर्जीवन ब्रेकिंग प्रणाली
- एयर कंडीशनिंग इकाई में स्वदेशी रूप से विकसित यूवी-सी लैम्प आधारित कीटाणुशोधन प्रणाली प्रदान की गई है, जो कंडीशन किए गए हवा से 99% हानिकारक बैक्टीरिया को निष्क्रिय करती है ताकि यात्रियों के क्षेत्र के अंदर स्वच्छता मानक बेहतर हो सकें।
- केंद्रीय नियंत्रण वाले स्वचालित प्लग डोर और पूरी तरह सील किए गए चौड़े गलियारे।
- सभी कोचों में सीसीटीवी।
- आपात स्थिति में यात्री और ट्रेन प्रबंधक/लोको पायलट के बीच संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट।
- दिव्यांगजन यात्रियों के लिए, प्रत्येक सिरे पर ड्राइविंग कोचों में विशेष शौचालय।
- केंद्रीयकृत कोच निगरानी प्रणाली, ताकि एयर कंडीशनिंग, सैलून लाइटिंग जैसी यात्री सुविधाओं की बेहतर स्थिति की निगरानी की जा सके।
- ऊपरी बर्थ पर चढ़ने को आसान बनाने के लिए एर्गोनोमिक रूप से डिजाइन की गयी सीढ़ी।

# एयरोस्पेस में आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम: गति शक्ति विश्वविद्यालय-एयरबस उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ

सूत्र/रे.स.ब्यू- एयरबस ने गुजरात के वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) में एयरोस्पेस अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का उद्घाटन किया। गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए भारत का अद्वितीय उद्योग-संचालित केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

यह केंद्र भारत के एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एयरबस और जीएसवी के बीच दीर्घकालिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और प्रतिभा विकास के माध्यम से भारत के एयरोस्पेस पारिस्थिति की तंत्र को मजबूत करना है। इस सह-शिक्षा केंद्र का एक प्रमुख केंद्र सतत विमानन ईंधन पर अनुसंधान एवं विकास करना और भविष्य की एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में छात्रों के नेतृत्व वाले नवाचारों को समर्थन देना होगा।

2024 में घोषित, इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमेयर ने महामहिम राजमाता शुभांगिनी-राजे गायकवाड़, जी एस वी की सदस्य और प्रोफेसर (डॉ.) मनोज चौधरी, कुलपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय की उपस्थिति में किया गया।

"गति शक्ति विश्वविद्यालय में इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भारत में एक सशक्त एयरोस्पेस पारिस्थिति की तंत्र के सह-निर्माण के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केंद्र अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार के प्रति एयरबस की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) में परिवर्तित करने जैसी अभूतपूर्व तकनीकों पर केंद्रित है। एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमेयर ने कहा कि हमें खुशी है कि एयरबस और जीएसवी के बीच यह सहयोग छात्रों को समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकास का नेतृत्व करने, भारत के भविष्य के विमानन परिदृश्य को आकार देने और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा।

जीएसवी के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने कहा कि हमारे माननीय कुलाधिपति श्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में, गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए उच्च कुशल मानव संसाधन और नई प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु उद्योग-प्रेरित नवाचार-आधारित दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल रहा है। एयरबस ने जीएसवी के साथ अपनी तरह की अनूठी उद्योग-अकादमिक साझेदारी स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो अब देश के लिए एक मिसाल बन गई है। सह-शिक्षण केंद्र का उद्घाटन देश में एयरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे साझा मिशन और साझेदारी को साकार करने की दिशा में एक और ठोस कदम है। इसके अतिरिक्त एयरबस चेयर प्रोफेसरशिप और एयरबस छात्रवृत्ति की स्थापना के लिए पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित यह समग्र क्षेत्र दृष्टिकोण 2047 तक विकसित भारत के लिए एक प्रमुख सहायक सिद्ध होगा।

2024 से, एयरबस और जीएसवी ने भारत में एक एकीकृत एयरोस्पेस इकोसिस्टम के आधारभूत तत्वों को परिपक्व करने के उद्देश्य से एक समग्र साझेदारी स्थापित की है। इस सहयोग में मेधावी और वंचित 45 छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से मानव पूंजी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता शामिल है, जिसमें एक तिहाई छात्रवृत्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, एयरबस ने स्नातक, स्नातकोत्तर और अल्पकालिक कार्यकारी कार्यक्रमों के विकास में सहयोग हेतु जीएसवी में एयरोस्पेस अध्ययन के लिए एक चेयर प्रोफेसर का पद भी स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, सतत विमानन समाधान विकसित करने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समझौते (जेएसए) के साथ साझेदारी का विस्तार उच्च-प्रभाव वाले अनुसंधान में भी हुआ है। यह पहल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) में परिवर्तित करने पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान प्रदान करती है, जिसमें भारत में विमानन ईंधन के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित, चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने हेतु जीएसवी की अनुसंधान क्षमताओं और एयरबस की औद्योगिक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाता है।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), परिवहन और रसद क्षेत्र में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे संसद के अधिनियम द्वारा 2022 में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। मांग-आधारित पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय को रेलवे, विमानन, राजमार्ग, बंदरगाह, समुद्री परिवहन, जहाजरानी, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और संपूर्ण रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क सहित संपूर्ण परिवहन क्षेत्र को कवर करने का दायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अश्विनी वैष्णव (रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) हैं।

# रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार: उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाएं स्वीकृत

सूत्र/रे.स.ब्यू- उत्तर प्रदेश में औड़िहार-वाराणसी नगर खंड पर तीसरी लाइन बिछाई जाएगी जिससे ट्रेन और माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी राजस्थान में रींगस-सीकर रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई में बढ़ोतरी और क्षेत्रीय विकास होगा मध्य प्रदेश में उज्जैन बाईपास लाइन से ट्रेनों के वापस मोड़ने (रिवर्सल) की समस्या समाप्त होगी और तीर्थयात्रियों के लिए संपर्क सुविधा बढ़ेगी देश में रेल नेटवर्क और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए भारतीय रेल ने तीसरी लाइन के निर्माण, दोहरीकरण और बाईपास अलाइनमेंट (भीडभाड वाले रेल यातायात मार्ग को वैकल्पिक उपमार्ग से गुजारने की योजना) सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका लक्ष्य परिचालन दक्षता और यात्री सुरक्षा बढ़ाना, यात्रा समय में कमी लाना और आम लोगों को सुगमता प्रदान करना है। इससे आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण रेल मार्ग पर सुचारू आवागमन सुनिश्चित होगा।

**उत्तर प्रदेश में 497.07 करोड़ रुपये की लागत से औड़िहार वाराणसी नगर के बीच 31.36 किलोमीटर की तीसरी लाइन**

भारतीय रेल ने उत्तर पूर्वी रेलवे के अंतर्गत औड़िहार वाराणसी नगर के बीच समर्पित तीसरी लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी है। इस व्यस्त खंड पर अभी काफी यात्री और माल ढुलाई संचालित होती है। इनमें सीमेंट, कोयला, खाद्यान्न, लोहा, इस्पात और औद्योगिक सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। तीसरी लाइन के निर्माण से प्रतिदिन दोनो दिशाओं से सात से अधिक अतिरिक्त रेलगाड़ी चल सकेगी और माल ढुलाई में वार्षिक स्तर पर 1.99 मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। इससे समग्र नेटवर्क परिचालन बढ़ेगा। योजना पूर्ण होने पर, लाइन की वर्तमान क्षमता मौजूदा 87.93 प्रतिशत से बढ़कर 102 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी, जिससे भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा

और लाखों यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। यह उन्नयन स्थानीय उद्योगों के लिए साजो-सामान लाने की सुविधा और पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गलियारे को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

**राजस्थान में 470.34 करोड़ रुपये की लागत से 50.06 किलोमीटर लंबे रींगस-सीकर रेल-खंड का दोहरीकरण-**

उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजस्थान में रींगस-सीकर रेलखंड के दोहरीकरण से इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मार्ग की क्षमता में काफी सुधार होगा। प्रतिदिन दोनों दिशाओं में पांच अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन और माल ढुलाई में 2.36 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ, यह परियोजना यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं में विश्वसनीयता और गति में सुधार लाएगी। इससे परिचालन दक्षता में वृद्धि के साथ ही राजस्थान के औद्योगिक और तीर्थ क्षेत्रों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी, जिसमें खाटू श्यामजी (सीकर) और सालासर बालाजी (चूरू) जैसे स्थलों तक पहुंचना और भी सुगम हो जाएगा। अभी इस रेलखंड की 77 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है, जिसके 2029-30 तक बढ़कर 210 प्रतिशत होने की संभावना है। दोहरीकरण से यह रेलखंड भविष्य में यातायात बढ़ोतरी को सुचारू तौर पर संभाल सकेगा। स्थानीय यात्री और व्यवसाय भी इस रेलखंड दोहरीकरण से लाभान्वित होंगे। इससे विलंब में कमी और समय पर रेल सेवा तथा माल ढुलाई में सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

**मध्य प्रदेश में 189.04 करोड़ रुपये की लागत से 8.60 किलोमीटर नईखेरी-चिंतामन गणेश को जोड़ने वाली उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन:**

पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत उज्जैन बाईपास लाइन परियोजना से वैकल्पिक उपमार्ग उपलब्ध होगा जिससे उज्जैन जंक्शन पर रेलगाड़ियों को वापस मोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और खंड की क्षमता और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह रेल गलियारा धार्मिक और पर्यटन यातायात को सुगम बनाएगा, विशेष रूप से वर्ष 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले को देखते हुए, इससे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और अन्य पूजनीय स्थलों पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध रेल आवागमन सुनिश्चित होगा। रेलगाड़ियों को वापस मोड़ने की आवश्यकता न होने से विलंब कम होगा और समय सारिणी की विश्वसनीयता सुधरेगी। विशेष रूप से अत्यधिक भीडभाड वाले त्योहारों के समय यह लोगो के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगा। इस परियोजना से दैनिक यात्री और माल ढुलाई सेवाओं का सुचारू संचालन भी सुनिश्चित होगा और मौजूदा तथा भविष्य दोनों ही मांग पूरी होगी। रेल-उपमार्ग से स्थानीय लोगों, दैनिक यात्रियों और तीर्थयात्रियों को तेज रेल परिवहन और बेहतर सेवा का लाभ मिलेगा।

ये रेल परियोजनाएं भारतीय रेलवे की समावेशी और संधारणीय परिवहन विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शाती हैं, जो संपर्क कमियों को दूर कर सेवा विश्वसनीयता में सुधार लाएगी और भारतीय रेल को आधुनिक, कुशल और नागरिक-केंद्रित भविष्य की ओर अग्रसर बनाएगी।

# होली पर भारतीय रेलवे का तोहफा: यात्रियों की सुविधा हेतु रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनों का संचालन

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय रेलवे ने आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों के लिए आरामदायक और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपने नेटवर्क पर 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। यह संख्या बढ़कर 1,500 तक हो सकती है। इन विशेष सेवाओं का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करना और प्रमुख गंतव्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। ये विशेष ट्रेनें मार्च के महीने में संचालित होने वाली हैं। पिछले वर्ष, 2025 में होली के लिए कुल 1,144 विशेष ट्रेनों के ट्रिप का संचालन किया गया था।

विभिन्न जोन के आधार पर, पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) सर्वाधिक 285 विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। इसके बाद पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) द्वारा पश्चिमी मार्गों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 231 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई गई है। मध्य रेलवे (सीआर) द्वारा 209 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) कुल 160 सेवाओं का संचालन करेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर रेलवे (एनआर) द्वारा 108 और उत्तर पश्चिम रेलवे (एनडब्ल्यूआर) द्वारा 71 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की योजना तैयार की गई है।

कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करते हुए, उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) द्वारा 66 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। वहीं, पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) और पूर्व तटीय रेलवे (ईसीओआर) दोनों ही 62-62 ट्रेनें चलाएंगे।

दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) द्वारा 47 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जबकि पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) ने 43 सेवाओं की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण रेलवे (एसआर) द्वारा 39 होली स्पेशल ट्रेनें और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) द्वारा 15 सेवाएं संचालित की जाएंगी। क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए कोंकण रेलवे (केआर) द्वारा 9 और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एनएफआर) द्वारा 2 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

# रेल मंत्रालय ने "बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाएँ" एवं "गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों और कार्गो-संबंधित सुविधाओं के माध्यम से रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स" के साथ सुधार एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया

## एक ऐतिहासिक कदम के तहत सामान्य कोचों पर विशेष ध्यान देते हुए, रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की निरन्तर सफाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा

सूत्र/पीआईबी- केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि वर्ष 2026 के दौरान "52 सप्ताह में 52 सुधार" करने के भारतीय रेल के संकल्प के अनुरूप, भारतीय रेल द्वारा दो नए सुधारों को स्वीकृति दी गई है और उनका कार्यान्वयन तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधार एक बारगी घटना नहीं, बल्कि एक सतत् प्रक्रिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इसका प्रभाव आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय रेल विश्व में दूसरी सबसे बड़ी माल परिवहन सेवा बन चुकी है, तथा पूरे तंत्र में नई पीढ़ी की ट्रेनों और कार्य करने के नए तरीकों का उद्भव हो रहा है।

### बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाओं के लिए सुधार

पहले सुधार की व्याख्या करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 से भारतीय रेल ट्रेनों, विशेषकर लंबी दूरी की ट्रेनों की समुचित एंड-टु-एंड सफाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत सफाई मुख्यतः आरक्षित कोचों तक सीमित थी, और रेलवे के इतिहास में पहली बार सामान्य कोचों की सफाई को पूर्ण रूप से प्रणाली में एकीकृत किया गया है।

रेलवे में जो ट्रेनें चलती हैं, विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों, उनकी प्रॉपर एंड-टू-एंड क्लीनिंग सुनिश्चित की जाएगी। इस रिफॉर्म के तहत जनरल कोचों की सफाई की जाएगी एवं ट्रेन के ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक कंटीन्यूअस सफाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पूर्व की "क्लीन ट्रेन स्टेशन" अवधारणा, जिसके अंतर्गत सीमित स्टेशनों पर गहन सफाई की जाती थी, को अब ट्रेन के प्रस्थान स्थल से लेकर गंतव्य स्थल तक निरन्तर सफाई मॉडल से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। शौचालय, कूड़ेदान, केबिन के आंतरिक भाग, जल उपलब्धता तथा यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली लाइट बंद होने जैसी छोटी विद्युत या यांत्रिक त्रुटियों का निरंतर समाधान किया जाएगा, जिससे यात्रियों को उल्लेखनीय रूप से बेहतर यात्रा वातावरण प्राप्त हो।

श्री वैष्णव ने कहा कि यह सुधार यात्रियों के यात्रा वातावरण को पूर्णतः बेहतर बनाने की सोच के साथ तैयार किया गया है। जोनल रेलवे के परामर्श से प्रत्येक जोन में लगभग चार से पाँच ट्रेनों मुख्यतः लंबी दूरी और अधिक यात्री आवागमन वाली-को अगले छह महीनों में क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में विभिन्न जोनों में कुल 80 ट्रेनों की पहचान की जा चुकी है, और तीन वर्षों की अवधि में यह सुधार भारतीय रेल की सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। ट्रेनों का चयन प्रबंधकीय स्तर पर क्षेत्रीय इनपुट और परिचालन मानकों के आधार पर किया गया है।

मंत्री महोदय ने विस्तार से बताया कि स्पष्ट रूप से परिभाषित सेवा स्तर समझौतों के अंतर्गत, सफाई की आवृत्ति निर्धारित करते हुए एक पूर्णतः प्रौद्योगिकी-सक्षम पेशेवर टीम की नियुक्ति की जाएगी। अत्यधिक भीड़-भाड़ के समय में अधिक बार तथा कम भीड़भाड़ के समय में तुलनात्मक रूप से कम आवृत्ति से सफाई की व्यवस्था होगी। शौचालयों की निरंतर सफाई, कचरा निष्पादन, केबिनेट की सफाई, चादर-कंबल इत्यादि प्रबंधन तथा संबंधित सेवाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।

उन्होंने आगे कहा कि चादर-कंबल इत्यादि वितरण, इनका संग्रहण और सफाई से संबंधित कार्य, जो पहले अलग-अलग एजेंसियों के बीच विभाजित थे, अब एकीकृत करके एक ही एजेंसी को सौंपे जाएंगे। निर्धारित स्टेशनों पर आरक्षित कोचों में तैनात कर्मचारी सामान्य कोचों में भी जाकर आरक्षित कोचों के समान सफाई मानक सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इसे रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन बताते हुए कहा कि पहली बार सामान्य कोचों की स्वच्छता पर इतना व्यापक और ठोस ध्यान दिया जा रहा है।

इस सुधार के अंतर्गत वॉर रूम नियंत्रण केंद्रों की स्थापना भी शामिल है, जहाँ सफाई गतिविधियों की एआई द्वारा उत्पन्न तसवीरों की निगरानी और विश्लेषण किया जाएगा। एआई-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से यह सत्यापित किया जाएगा कि सफाई उचित रूप से की गई है या नहीं, और यदि नहीं, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दीर्घ परिचालन अनुभव के आधार पर विस्तृत अध्ययन के पश्चात मार्ग-विशिष्ट टीमों का गठन किया जाएगा। इन टीमों में बहु-कौशल कर्मी शामिल होंगे, जो सफाई के अतिरिक्त छोटे-मोटे यांत्रिक एवं विद्युत मरम्मत कार्यों का निपटान करने में भी सक्षम होंगे, जिससे एकीकृत ऑन-बोर्ड सेवा प्रदान की जा सके।

### माल ढुलाई लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बेहतर सुविधाओं के साथ अधिक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल

दूसरे सुधार का रुख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह वर्ष 2022 में शुरू की गई गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति पर आधारित है, जिसने कार्गो टर्मिनल अनुमोदन प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से सरल बनाया। जो कार्य पहले छह वर्ष में पूर्ण होते थे, वे लगभग तीन माह में पूरे होने लगे और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, सिग्नलिंग योजना और विद्युत योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 124 मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनलों का विकास हुआ, जिनकी अनुमानित यातायात क्षमता लगभग 200 मिलियन टन और वार्षिक राजस्व क्षमता लगभग 20,000 करोड़ आंकी गई है।

श्री वैष्णव ने कहा कि तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर चार माह तक हितधारकों से परामर्श के पश्चात एक व्यापक रूप से उन्नत सुधार को स्वीकृति दी गई है। इस सुधार के साथ, वर्तमान 124 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों की संख्या अगले पाँच वर्षों में 500 से अधिक होने की अपेक्षा है। उन्होंने इसे वर्ष 2022 के सुधार से भी अधिक व्यापक और मूलभूत सुधार बताया।

सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कार्गो टर्मिनलों के भीतर प्रसंस्करण की सुविधा का एकीकरण है, जिससे उन्हें "कार्गो प्लस प्रोसेसिंग" हब में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीमेंट क्लिंकर को जीसीटी तक लाकर उसी टर्मिनल परिसर में सीमेंट में परिवर्तित किया जा सकता है, तत्पश्चात उसकी पैकेजिंग या रेडी-मिक्स कंक्रीट वाहनों के माध्यम से प्रेषण किया जा सकता है। इसी प्रकार, खाद्यान्न प्रसंस्करण, स्टफिंग एवं डी-स्टफिंग तथा अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियाँ अब टर्मिनल परिसर के भीतर ही संचालित की जा सकेंगी। इससे सामग्री को टर्मिनल तक लाने से पूर्व अन्यत्र प्रसंस्करण की आवश्यकता समाप्त होगी, कृत्रिम अवरोध दूर होंगे और अतिरिक्त माल यातायात रेलवे की ओर आकर्षित होगा।

उन्होंने कहा कि अनेक कम उपयोग किए गए माल शेडों को जीसीटी और कार्गो सुविधाओं के रूप में विकसित किया जाएगा। पूर्व नीतियों के अंतर्गत विकसित पुरानी साइडिंग्स को सरल जीसीटी ढांचे में स्थानांतरित किया जा सकेगा। टर्मिनलों और मुख्य लाइनों के बीच छोटे संपर्क खंडों पर, जहाँ उच्च उपकरण लागत के कारण निजी संचालकों को पटरियों और विद्युत प्रणालियों के रखरखाव में कठिनाई होती थी, वहाँ अब रेलवे वैकल्पिक रूप से भुगतान के आधार पर रखरखाव का कार्य करेगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा और रखरखाव की जिम्मेदारी स्पष्ट होगी।

इस सुधार के अंतर्गत वाई-कनेक्शन और रेल-ओवर-रेल संरचनाओं सहित, विस्तृत कॉमन यूजर सुविधाओं की अनुमति प्रदान की गई है। मल्टी-जीसीटी कनेक्टिविटी को औपचारिक रूप दिया गया है, जिससे यदि किसी मौजूदा खंड पर नया टर्मिनल विकसित किया जाता है तो कनेक्टिविटी से इनकार न किया जा सके, जिससे पूर्व में उत्पन्न होने वाले विवाद और न्यायिक वाद-विवाद की स्थिति से बचा जा सके। विवाद निवारण हेतु एक रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत टर्मिनल डेवलपर्स और रेलवे अधिकारियों के बीच मासिक अथवा माइलस्टोन-आधारित संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों के परिणामस्वरूप संयुक्त टिप्पणियाँ तथा "नो डिस्प्यूट सर्टिफिकेट" जारी किए जाएंगे, जिससे मध्यस्थता या अदालती मामलों की आवश्यकता घट जाएगी।

मानक लेआउट को नीति में समाहित किया गया है, और जो आवेदक मानक डिजाइन अपनाएंगे उन्हें स्वचालित स्वीकृति प्रदान की जाएगी, ठीक उसी प्रकार जैसे दूरसंचार सुधार मॉडल में मानकीकरण से स्वीकृति समयसीमा में उल्लेखनीय कमी आई थी। जीसीटी और कार्गो-संबंधित सुविधाओं के लिए अनुबंध अवधि को 35 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक निवेश और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

मंत्री महोदय ने अनुमान व्यक्त किया कि उन्नत माल परिवहन के माध्यम से यह सुधार तीन वर्ष की अवधि में लगभग ₹30,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने नवंबर दिसंबर में प्रारंभ किए गए सीमेंट परिवहन सुधार का उदाहरण देते हुए कहा कि थोक सीमेंट की मात्रा दोगुनी से अधिक हो गई है। जनवरी में यह आंकड़ा लगभग 95,000 टन तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह लगभग 40,000 टन पर था। उन्होंने उल्लेख किया कि रेलवे-आधारित थोक सीमेंट परिवहन से लागत में उल्लेखनीय कमी आई हैं जम्मू और कश्मीर में लगभग 30% तक तथा मिजोरम में लगभग 50% तक-साथ ही वैज्ञानिक परिवहन विधियों के माध्यम से प्रदूषण में भी कमी आई है।

### अन्य आगामी सुधार

श्री वैष्णव ने आगे कहा कि सात और सुधार प्रक्रिया में हैं, जिनमें से दो का अनावरण इस माह किया जाएगा तथा अन्य तीन का प्रारंभ मार्च माह की शुरुआत में किया जाएगा। 30-40 अतिरिक्त सुधारों पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। यात्री सेवाओं और माल लॉजिस्टिक्स में संरचनात्मक सुधारों के साथ, भारतीय रेल एक महत्वाकांक्षी वर्षव्यापी परिवर्तन एजेंडा की शुरुआत कर रहा है।

# देश के रेल नेटवर्क में होगा 389 किमी का इजाफा, कैबिनेट ने दी तीन अहम परियोजनाओं को हरी झंडी

सूत्र/पीआईबी- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रेल मंत्रालय की तीन (3) परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिनकी कुल लागत 18,509 करोड़ रुपये (लगभग) है। विस्तारित पटरी क्षमता से गतिशीलता काफी बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की संचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बेहतर होगी। अतिरिक्त पटरियां बिछाने के प्रस्ताव को आसान बनाने और भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नये भारत की कल्पना के मुताबिक हैं, जो क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएगा। इसके लिए इलाके में बड़े पैमाने पर विकास होगा, जिससे उनके रोजगार/स्व-रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर बनाई गई है, जिसमें एकीकृत योजना और साझेदार परामर्श के जरिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये परियोजनाएं लोगों, सामान और सेवाओं को लाने-ले जाने के लिए आसान सम्पर्क देंगे।

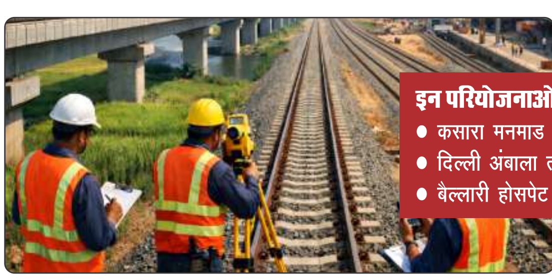


दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के 12 जिलों को कवर करने वाली तीन (3) परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 389 किलोमीटर बढ़ जाएगा।

प्रस्तावित अतिरिक्त पटरियां बिछाने की परियोजना से लगभग 3,902 गांवों तक सम्पर्क बढ़ेगा, जिनकी आबादी लगभग 97 लाख है। प्रस्तावित क्षमता बढ़ाने से देश भर के अनेक खास पर्यटन स्थलों तक रेल सम्पर्क बेहतर होगा, जिनमें भावली डैम, श्री घाटनदेवी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री माता वैष्णो देवी कटरा/श्रीनगर, और हम्पी (एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट), बल्लारी किला, दारोजी स्लॉथ बेयर सैंक्चुरी, तुंगभद्रा डैम, केंचनगुड्डा, और विजया विट्ठल मंदिर वगैरह जैसे खास आकर्षण शामिल हैं।

प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, स्टील, लोह अयस्क, सीमेंट, लाइमस्टोन/बॉक्साइट, कंटेनर, अनाज, चीनी, उर्वरक, पीओएल वगैरह जैसी चीजों के परिवहन के लिए जरूरी मार्ग हैं। क्षमता बढ़ाने के काम से 96 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) के अतिरिक्त माल की ढुलाई होगी। पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा का कम उपयोग करते हुए परिवहन का तरीका अपनाकर रेलवे को जलवायु उद्देश्यों को पाने और देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, तेल आयात (22 करोड़ लीटर) कम करने और कार्बन उत्सर्जन (111 करोड़ किलोग्राम) कम करने में मदद मिलेगी, जो 04 (चार) करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

# केरल में 160 किमी प्रति घंटे की हाई-स्पीड क्षमता वाली 7 परियोजनाओं के लिए डीपीआर सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई

## पूरे भारत में 11 वर्षों में 130 से अधिक किमी प्रति घंटे की अनुभागीय गति ट्रैक लगभग 4 गुना बढ़ी, जो 5,036 किमी से बढ़कर 23,477 किमी हो गई है और अब कुल नेटवर्क का 22.2% कवर करती

सूत्र/पीआईबी- सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि रेल मंत्रालय ने केरल में रेल अवसंरचना को सशक्त बनाने और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में 160 किमी प्रति घंटे की हाई-स्पीड क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से 7 अहम परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं से केरल के रेल तंत्र के आधुनिकीकरण और यात्रा अवधि में कमी लाने की उम्मीद है।

स्वीकृत परियोजनाओं में होरनूर मैंगलुरु तृतीय एवं चतुर्थ लाइन (307 किमी), कोयंबटूर शोरनूर तृतीय व चतुर्थ लाइन (99 किमी), शोरनूर एर्नाकुलम तृतीय लाइन (106 किमी), एर्नाकुलम कायंकुलम (कोट्टायम मार्ग) तृतीय लाइन (115 किमी), कायंकुलम तिरुवनंतपुरम तृतीय लाइन (105 किमी), तिरुवनंतपुरम नागरकोइल तृतीय लाइन (71 किमी) तथा तुरवूर अंबलप्पुझा दोहरीकरण (46 किमी) शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से रेल नेटवर्क को अधिक सक्षम बनाने, ट्रेनों की गति बढ़ाने, यात्रा समय घटाने और राज्य में पर्यटन एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है। डीपीआर तैयार होने के बाद राज्य सरकार, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श कर आगे की स्वीकृतियां ली जाएंगी।

# डिजिटल सख्ती का असर: 2025 में 3.03 करोड़ संदिग्ध यूज़र आईडी निष्क्रिय, असली यात्रियों को मिली निर्बाध बुकिंग

सूत्र/पीआईबी- सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रेल की आरक्षण टिकट बुकिंग प्रणाली एक सुदृढ़ और अत्यंत सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी मंच है, जो उद्योग-मानक, अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा नियंत्रणों से सुसज्जित है। इंटरनेट के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग में हैकिंग उपकरणों द्वारा स्वचालित ढंग से फॉर्म भरे जाने से रोकने तथा धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और प्रणाली को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने हेतु भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

**1.तत्काल टिकट बुकिंग हेतु आधार प्रमाणीकरण** - तत्काल बुकिंग में दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग हेतु आधार-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन लागू किया गया है। तत्काल टिकट बुकिंग की समय-संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता की अनन्यता का त्वरित सत्यापन करता है। यह अनन्यता की शर्त लागू कर फर्जी अथवा अनधिकृत एजेंट - नियंत्रित मल्टी-यूजर अकाउंट के सृजन एवं संचालन को रोकने में सहायक है। यह उपाय अकाउंट-मल्टीप्लिकेशन और स्वचालित दुरुपयोग के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे तत्काल टिकटों का निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित होता है। इससे वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट उपलब्धता में सुधार हुआ है तथा ऑनलाइन तत्काल बुकिंग प्रणाली में पारदर्शिता को सुदृढ़ किया गया है।

**2. एप्लिकेशन स्तर सुरक्षा नियंत्रण** - स्क्रिप्टिंग, ब्रूट-फोर्स अटैक तथा डीडीओएस (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस) हमलों की रोकथाम हेतु बहु-स्तरीय कैप्चा (कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कम्प्यूटर्स एंड ह्यूमन्स अपार्ट) तंत्र सहित विभिन्न एप्लिकेशन-स्तरीय सुरक्षा नियंत्रण लागू किए गए हैं। एप्लिकेशन सुरक्षा कमजोरियों के प्रबंधन के लिए ओडब्ल्युएएसपी (ओपन वेब एप्लिकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट) दिशानिर्देशों के अनुसार कई सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए भारतीय रेल ने स्थिर सामग्री को ऑफलोड करने और इंटरनेट टिकट बुकिंग वेबसाइट प्रणाली पर सीधे ट्रैफिक को कम करने हेतु कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) लागू किया है। इसके अलावा, एंटी-बॉट समाधान जैसे कि एकामाई (AKAMAI) का प्रयोग किया गया है, जो असत्यापित उपयोगकर्ताओं को फिल्टर करता है और इंटरनेट टिकट बुकिंग वेबसाइट प्रणाली पर दुर्भावनापूर्ण / संदिग्ध प्रयासों को कम करने में मदद करता है, जिससे वास्तविक यात्रियों के लिए सुचारू बुकिंग सुनिश्चित होती है। इससे दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण में सहायता मिलती है। सिस्टम को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए नेटवर्क फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल जैसे कई सुरक्षा परतों का उपयोग किया गया है।

**3.नेटवर्क और अवसंरचना स्तर सुरक्षा नियंत्रण-** पूरे आईसीटी (इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज) अवसंरचना को उच्च उपलब्धता मोड पर तैनात किया गया है, जिससे विफलताओं को न्यूनतम किया जा सके। सिस्टम को उद्योग-मानकों के अनुरूप, अत्याधुनिक और डेटा सेंटर ग्रेड नेटवर्क एवं सुरक्षा उपकरणों द्वारा सुरक्षित किया गया है, जिनमें नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल शामिल हैं। सिस्टम को वॉल्यूम-आधारित डीडीओएस (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ

सर्विस) हमलों से भी सुरक्षित किया गया है, जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) स्तर, डीडीओएस डिटेक्शन और शमन सेवाओं का उपयोग किया गया है। यह बहु-आईएसपी तंत्रों के माध्यम से संचालित होता है, जिनकी संयुक्त डीडीओएस शमन क्षमता लगभग 30 जीबीपीएस है। उन्नत सुरक्षा, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव, वेब ट्रैफिक लोड में कमी, संसाधन अनुकूलन और खतरे को कम करने के लिए एंटरप्राइज स्तर की कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन), एंटी-बॉट, सुरक्षित डीएनएस और वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (डब्ल्यूएएफ) सेवाएँ तैनात की गई हैं। व्यापक साइबर खतरा खुफिया सेवाओं के लिए, रेलटेल को डीप-डार्क वेब निगरानी, डिजिटल जोखिम सुरक्षा और घटना प्रतिक्रिया सुधार के कार्यो के लिए नियुक्त किया गया है।

**4. भौतिक सुरक्षा नियंत्रण सिस्टम**- नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित कैप्टिव डेटा सेंटर सुविधा में स्थापित किया गया है, जिसे सीसीटीवी निगरानी और सीमित भौतिक प्रवेश के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। यह सुविधा आईएसओ 27001 (आईएसएमएस) प्रमाणित है।

**5. सुरक्षा ऑडिट और निगरानी** - सुरक्षा संबंधी घटनाओं और घटनाक्रम की 24×7 निगरानी के लिए सिस्टम को सीईआरटी-इन टीएसएपी (थ्रेट एवं सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स) के साथ एकीकृत किया गया है। सिस्टम को सीईआरटी-इन के "मधु-संजाल" के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें सीईआरटी-इन ने हमलावरों के व्यवहार, संदिग्ध घटनाओं/घुसपैठ प्रयासों की निगरानी, उनकी रणनीतियों का अध्ययन करने और साइबर खतरों के खिलाफ रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हनीपॉट सेंसर तैनात किया है। सुरक्षा घटनाओं का पता लगाने और इन्हें न्यूनतम करने के लिए परिसर में तैनात सुरक्षा टीम द्वारा सिस्टम की सुरक्षा लॉग निगरानी की जा रही है।

6- प्रशासनिक उपाय अनधिकृत पहुँच को रोकने और वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध बुकिंग सुनिश्चित करने हेतु कई धोखाधड़ी-रोधी उपाय अपनाए गए हैं।

- यूजर अकाउंट्स का सख्त पुनः सत्यापन और जाँच की गई है। वर्ष 2025 में लगभग 3.03 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी निष्क्रिय की गई हैं।
- आरक्षण प्रणाली के नियमित सुरक्षा ऑडिट सीईआरटी-इन द्वारा नामांकित सूचना सुरक्षा ऑडिट एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा, टिकटिंग प्रणाली से संबंधित इंटरनेट ट्रैफिक की लगातार निगरानी सीईआरटी-इन और नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) द्वारा साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए की जाती है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर 3.99 लाख संदिग्ध बुकिंग से संबंधित 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
- वर्ष 2025 में 12,819 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए हैं।

**पिछले छह महीनों के दौरान ई-टिकटिंग प्रणाली तक पहुँचने के संदर्भ में असत्यापित प्रयासों के अस्वीकृत होने का विवरण इस प्रकार है:**

**दिसम्बर 2025**
14.28 अरब अनुरोधों में से 07.25 अरब अनुरोध स्वचालित बॉट्स द्वारा किए गए थे।

**नवम्बर 2025**
20.07 अरब अनुरोधों में से 14.03 अरब अनुरोध स्वचालित बॉट्स द्वारा किए गए थे।

**अक्तूबर 2025**
24.04 अरब अनुरोधों में से 17.00 अरब अनुरोध स्वचालित बॉट्स द्वारा किए गए थे।

**सितम्बर 2025**
19.04 अरब अनुरोधों में से 12.05 अरब अनुरोध स्वचालित बॉट्स द्वारा किए गए थे।

**अगस्त 2025**
11.04 अरब अनुरोधों में से 05.07 अरब अनुरोध स्वचालित बॉट्स द्वारा किए गए थे।

**जुलाई 2025**
09.06 अरब अनुरोधों में से 05.03 अरब अनुरोध स्वचालित बॉट्स द्वारा किए गए थे।

# पूर्वोत्तर विकास को नई गति, गुवाहाटी स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का शुभारंभ

सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल संपर्क को मजबूत करते हुए और पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देते हुए, रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ब्लेंडेड हॉस्पिटैलिटी सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सैरांग और सिलचर के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा, सिलचर से सांसद श्री परिमल सुकलाबैद्य, राज्यसभा सदस्य श्री कनाद पुरकायस्थ, और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

सैरांग - सिलचर पैसेंजर रेलगाड़ी मिजोरम की राजधानी को असम की बराक घाटी से सीधे जोड़ेगी। इससे क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार होगा और विद्यार्थियों, दैनिक यात्रियों और मरीजों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा मिलेगी। इसी समय, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आधुनिक हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं यात्रियों के आराम को बढ़ाएंगी और बेहतर, स्वच्छ और ग्राहक-अनुकूल यात्रा का अनुभव देंगे। इन सेवाओं में स्लीपिंग पॉड्स, आधुनिक एयर-कंडीशन्ड लाउंज और मल्टी-कुजीन रेस्टोरेंट शामिल हैं। ये सुविधाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक माहौल मिले, जिससे स्टेशन की कुल उपयोगिता बेहतर होगी।

इस अवसर पर संबोधन में श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में इस क्षेत्र के लिए रेल फंडिंग में काफी बढ़ोतरी की है। इसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में 11,486 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग ₹72,468 करोड़ की परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जो संपर्क सुविधा और अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास को दिखाती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फोकस प्रधानमंत्री के इस विश्वास को दर्शाता है कि पूर्वोत्तर का विकास ''विकसित भारत'' के लिए जरूरी है और हर क्षेत्र को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रेल संपर्क न केवल यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाता है, बल्कि आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ावा देता है। इससे सामान की आवाजाही आसान होती है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार खुलते हैं।

श्री वैष्णव ने बताया कि बैराबी-सैरंग रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। इस बढ़े हुए फोकस के तहत पूरी की गई यह ऐतिहासिक और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण परियोजना रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए इस रेल लिंक को अतिरिक्त ट्रेन सेवाओं के साथ और बेहतर बनाया जाएगा, जिससे मिजोरम से असम और उससे आगे का संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि सैरंग और सिलचर के बीच नई यात्री रेलगाड़ी सेवा क्षेत्रीय एकीकरण में काफी सुधार करेगी। इससे दक्षिणी असम, मिजोरम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के निवासियों को फायदा होगा।

श्री लालदुहोमा ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मिजोरम और असम को जोड़ने वाली विभिन्न रेल परियोजनाओं और प्रयासों की जानकारी दी, जिनसे इस क्षेत्र को फायदा होगा। पिछले एक दशक में, पूर्वोत्तर का रेलवे मानचित्र तेजी से बदला है, लंबे समय से अटकी परियोजनाएँ पूरी हुई हैं और राज्यों की राजधानियाँ धीरे-धीरे राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ रही हैं। पिछले वर्ष मिजोरम की 51 किमी लंबी बैराबी-सैरंग ब्रॉड-गेज लाइन शुरू होने से आइजोल पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर आया, और अब सिलचर तक यात्री सेवाओं के विस्तार से यह संपर्क सुविधा और आगे बढ़ी है। इससे पूरे क्षेत्र में आवाजाही बेहतर होगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

# महाप्रबंधक ने कटनी साउथ-ब्यौहारी रेल खण्ड का नियमित निरीक्षण किया

सूत्र/रे.स.ब्यू- पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय ने मंगलवार 3 फरवरी 2026 को कटनी साउथ-ब्यौहारी रेल खण्ड का संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य रेल संरक्षा, परिचालन गुणवत्ता और अधोसंरचना के साथ निर्माणाधीन कार्यो की प्रगति की समीक्षा करना था। महाप्रबंधक ने इस रेल खण्ड पर स्थित स्टेशनों, रेल पुलों, ओएचई प्रणाली और सिग्नल एवं दूरसंचार व्यवस्था की गहन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने रेल खण्ड में ट्रेनों की रनिंग गुणवत्ता और ट्रैक पेट्रोलिंग की स्थिति का भी जायजा लिया।

निरीक्षण की शुरुआत कटनी साउथ स्टेशन से हुई, जहां प्रमुख मुख्य अभियंता और जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। महाप्रबंधक ने महानदी रेल पुल का निरीक्षण किया और खन्ना बंजारी स्टेशन पर ट्रैक कर्व की जांच की। इसी अवसर पर उन्होंने खन्ना बंजारी में नवनिर्मित आवासीय परिसर और वरिष्ठ खंड अभियंता कार्यालय का उद्घाटन किया। महरई स्टेशन पर उन्होंने ट्रैकमैन कर्मचारियों से संवाद कर संरक्षा संबंधित विषयों पर चर्चा की और पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के अंत में ब्यौहारी स्टेशन पर स्टेशन लॉबी, परिसर, सर्कुलेटिंग एरिया और ''एक स्टेशन एक उत्पाद'' स्टॉल की समीक्षा की गई। महाप्रबंधक ने यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया और स्टेशन में नवनिर्मित वीआईपी कक्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यालय एवं मंडल के विभिन्न प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम मध्य रेल रेल संरक्षा को सुदृढ़ करने और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

# पूर्वोत्तर रेलवे को स्क्रैप निस्तारण के फलस्वरूप कुल रु. 169.33 करोड़ की आय

सूत्र/रे.स.ब्यू- पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन स्क्रैप निस्तारण के क्षेत्र में निरन्तर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है। स्क्रैप निस्तारण से रेल राजस्व की प्राप्ति के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को गति मिली है।

स्क्रैप निस्तारण के परिणामस्वरूप रेल परिसर एवं रेल लाइनों के किनारे पड़ी निरोंत सामग्रियों के निस्तारण से ये स्थल स्वच्छ एवं साफ-सुथरे हो रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में माह जनवरी, 2026 तक 'मिशन जीरो स्क्रैप' के तहत स्क्रैप निस्तारण से रू. 169.33 करोड़ की आय हुई है तथा माह जनवरी, 2026 में स्क्रैप निस्तारण से रू. 23.14 करोड़ की आय हुई है।

भारत सरकार के कार्यक्रम 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत रेल परिसरों तथा रेल पटरियों के किनारे पड़े हुये निष्प्रयोज्य सामग्री, परित्यक्त इमारतों एवं आवासों की पहचान कर निस्तारण किया गया है, जिससे रेल राजस्व प्राप्त होने के साथ ही रेल परिसर तथा रेल पटरियों को स्वच्छ रखने में भी सफलता मिली है।

**समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा**

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

## पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सद्स्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

**सहयोग राशि:**

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पंजिकृत कार्यालय
502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिर्पोटर) कार्यालय 8439 आर्य नगर पहाड़गंज दिल्ली-55

# Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project Experience Lays a Strong Foundation for India's Future High-Speed Rail Network

## *406 Trains Operating Daily on EDFC and WDFC, Creating Additional Capacity on Conventional Rail Network*

**Source/RSB-** Union Minister for Railways, Information & Broadcasting and Electronics & Information Technology, Shri Ashwini Vaishnaw said in loksabha that presently, the Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) Project (508 km) is under execution with technical and financial assistance from Government of Japan. The MAHSR project is planned and constructed on a elevated viaduct. The design for stations on the corridor provides for security measures like controlled entry points, baggage scanners, DFMDs (Door Frame Metal Detectors), CCTV(Close Circuit Television) cameras etc.

The experience and technical capabilities being developed through the MAHSR project, particularly in track construction, advanced signalling, Rolling Stock manufacturing & maintenance, project management etc. are expected to provide a strong foundation for future high-speed rail corridors in the country. With gain of such expertise, India will strengthen its position for planning and decision making in HSR Sector.

## MAHSR Designed for High-Frequency Operations with Fares Competitive with Existing Rail/Air Travel

### Progress of Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project

The Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) Project (508 km) is passing through the States of Gujarat, Maharashtra and Union Territory of Dadra & Nagar Haveli with 12 stations planned at Mumbai, Thane, Virar, Boisar, Vapi, Billimora, Surat, Bharuch, Vadodara, Anand, Ahmedabad & Sabarmati.

Entire land (1389.5 Ha.) for MAHSR project has been acquired. All Statutory Clearances have been obtained. All 1651 utilities have been shifted. The delay in land acquisition in the State of Maharashtra has impacted the project till 2021. The land acquisition picked up in 2022 in Maharashtra.

Out of total 12 stations, foundation works has been completed at 8 stations (Vapi, Bilimora, Surat, Bharuch, Anand, Vadodara, Ahmedabad, and Sabarmati). In Maharashtra section, foundation work is in progress at 3 stations (Thane, Virar, Boisar) & excavation work at BKC station is near completion and Casting of base slab started.

17 river bridges have been completed. Work is in advance stage for 4 major river bridges (Narmada, Mahi, Tapti and Sabarmati) in Gujarat & in progress in 4 river bridges in Maharashtra. Work on Depots (Thane, Surat and Sabarmati) is in full swing. Civil works at Bandra Kurla Complex (BKC) are progressing satisfactorily. Excavation works have achieved about 91% progress, and concreting works are at various stages, with 100% completion of the basement slab at Level-4. The work of the under-sea tunnel (approximately 21 km) has commenced, out of which 4.8 km of tunnel between Ghansoli and Shilphata in Maharashtra has been completed.

In line with the Make in India and Aatmanirbhar Bharat initiatives, Indian Railways is promoting indigenous manufacturing of high-speed rail systems & components to reduce import dependence. Building on the success of Vande Bharat, Integral Coach Factory (ICF) in collaboration with M/s Bharat Earth Movers Limited (BEML) is designing & manufacturing high-speed train sets with a design speed of 280 kmph.

Land acquisition for the project has been carried out in accordance with applicable laws, and affected persons have been compensated as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act and relevant State policies. Rehabilitation and resettlement measures, including additional benefits and solatium, have been undertaken in coordination with State Governments.

The MAHSR corridor is designed for high-frequency operations with substantial passenger-carrying capacity. Ticket pricing is proposed to be competitive with respect to existing rail/air travel options. The viability of the project has been assessed on a long-term basis, taking into account projected passenger demand, economic benefits, time savings and regional development.

The Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) Project (508 km) is the only HSR Project under execution with technical and financial assistance from Government of Japan. Expenditure amounting to ₹ 86,939/- crore has been incurred on the project till 31.12.2025.

### Dedicated Freight Corridors

Ministry of Railways has taken up construction of two Dedicated Freight Corridors (DFC) viz. Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) from Ludhiana to Sonnagar (1337 Km) and the Western Dedicated Freight Corridor (WDFC) from Jawaharlal Nehru Port Terminal (JNPT) to Dadri (1506 Km) at a total cost of ₹ 1,24,005 Cr. The work on EDFC has been completed and commissioned. In WDFC, 1404 RKm out of total 1506 RKm has been completed and commissioned. The balance work on WDFC from Vaitarna-JNPT section (102 Rkm) has been taken up.

### Indigenization & Capacity Building

- Long-span steel truss girders are being fabricated in Indian workshops, supported by analytical modelling and field measurements to strengthen domestic HSR design capability.
- Heavy construction machinery used for full-span launching has been indigenised and is now being manufactured in India.
- Most slab track materials and specialized track machines are being developed and produced by Indian manufacturers, boosting domestic manufacturing capability.
- Design variations and detail regarding dynamic analysis are being handled by Indian agencies in collaboration with IITs, with advanced dynamic analysis tools and design charts developed to build long-term HSR expertise.

### Innovation

- Full-span launching method adopted for the first time in India for launching 40 m prestressed box girders (~1000 MT), enabling faster launching within 16 hours.
- Indigenous noise barriers being installed along the elevated corridor to minimise noise for nearby residents.
- Advanced simulation tools for OHE-pantograph interaction and Simulation model for designing of traction power supply developed with IIT Delhi for accurate design and planning.
- Underground station is being constructed with provision for a future 90 m high building on the same foundation.
- Indigenously developed Rail Turnover Prevention Device (RTPD) introduced to enhance safety during derailments.

### Training

- Indian Engineers and Skilled workers (approx. 1000 nos.) have been trained for Japanese methodology and presently, track works are being executed under their supervision.
- A Special Track training facility has been created at Surat for training and regular refresher courses.

### Stations

- HSR stations are being designed as city gateways reflecting local identity, with advanced security features such as controlled entry points, baggage scanners, Door Frame Metal Detectors (DFMDs) and Closed-Circuit Television (CCTV) surveillance.
- Safety-focused design includes anti-vibration measures, wind-pressure management in station roofs and provisions like anti-vibration hangers, clamps and bolting plates integrated during construction.
- Passenger convenience is ensured through ample parking, drop-off areas and seamless multimodal connectivity with coordinated city master planning.
- Sustainable and energy-efficient features aligned with Indian Green Building Council (IGBC) Platinum standards.

### Geo-technical investigation

- Greater emphasis has been put on Geo Technical Investigations (GTI) to be sure of structural adequacy and to rule out possibility of geological surprises.
- The GTI has been generally carried out at 100 m, and at shorter intervals in case of special structures.
- A new geo tech lab has also been been set up

### Safety and security

- A high level of security has been adopted for operational areas and buildings housing sensitive equipment to ensure passenger safety.
- Civil engineering structures are designed and constructed as per best international practices, with designs validated by a Japanese High-Level Committee.
- To enhance earthquake safety, structures have been designed considering relevant seismic zones, with steel and damper stoppers provided on viaducts and bridges to prevent dislodgement, along with installation of an Earthquake Early Warning System (EQEWS).

# श्री हरि शंकर वर्मा ने रेलवे बोर्ड के सदस्य (ऑपरेशंस एवं व्यवसाय विकास) का कार्यभार संभाला

सूत्र/रे.स.ब्यू- श्री हरि शंकर वर्मा, 1987 बैच के आईआरटीएस अधिकारी, ने रेलवे बोर्ड के सदस्य (ऑपरेशंस एवं व्यवसाय विकास) और भारत सरकार के पदेन सचिव का पदभार संभाल लिया है। इस पद को संभालने से पहले वे रेलवे बोर्ड में महानिदेशक (सुरक्षा) के रूप में कार्यरत थे।

अपने शानदार करियर के दौरान श्री वर्मा ने भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, जिनमें शामिल हैं : अपर मंडल रेलवे प्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबईय मंडल रेलवे प्रबंधक, सलेम डिविजन, दक्षिण रेलवेय मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबईय प्रधान मुख्य अ परेशंस मैनेजर, हुबली, दक्षिण-पश्चिम रेलवे और महानिदेशक, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, लखनऊ। इन सभी पदों पर रहते हुए श्री वर्मा ने कई रिकॉर्ड/उपलब्धियां हासिल कीं।

भारतीय रेलवे के महानिदेशक (सुरक्षा) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे के सुरक्षा रिकॉर्ड को नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया। प्रक्रिया सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है।

श्री वर्मा को दो बार माननीय रेल मंत्री पुरस्कार और महाप्रबंधक स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया और इटली से प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उन्हें रेलवे यातायात एवं प्रबंधन के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है।

# रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए मिला पर्याप्त बजट - वर्ष 2026-27 में 350 किलोमीटर से अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूरे करने का लक्ष्य।

सूत्र/रे.स.ब्यू- वर्ष 2025-26 में रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए पर्याप्त बजट प्रदान किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर रेल विकास के लिए अनेक कार्य प्रगति पर है। नई लाइन, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। क्षमता बढ़ोतरी के लिए कार्य त्वरित गति के साथ निष्पादित किए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में वर्ष 2024-25 में 70 किलोमीटर निर्माण परियोजनाओं को पूरा किया गया तथा इस वर्ष अभी तक 94 किलोमीटर नई लाइन एवं दोहरीकरण के कार्य पूरे किए गए है तथा मार्च 2026 तक 29 किलोमीटर का कार्य और पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्ष 2026-27 में 350 किलोमीटर से अधिक नई लाइन, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन के कार्य पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष 2026-27 में रेलवे को अभी तक का सबसे अधिक रिकार्ड 2.78 लाख करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में पहली बार 10 हजार करोड़ रूपए से अधिक 10228 करोड़ रूपए प्रदान किए गए है। हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के निर्माण परियोजनाओं की प्रगति में निधि के कारण कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। सभी कार्य सुगमता से प्रगति करेंगे।

उत्तर पश्चिम रेलवे में जयपुर-सवाई माधोपुर दोहरीकरण, आरडीएसओ डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक, तरंगा हिल-आबु रोड़ नई लाईन सहित लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक के नई लाइन, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन के कार्य प्रगति पर है और अनुपगढ़-बीकानेर नई लाईन, रास-बिलाड़ा नई लाईन, बठिंडा-हनुमानगढ़-सुरतगढ़-बीकानेर दोहरीकरण सहित 1500 किलोमीटर से अधिक के कार्य स्वीकृति के विभिन्न चरणों में है। इसके साथ ही बीकानेर बाईपास, खाटू श्यामजी-सालासर-सुजानगढ़ नई लाईन, देवगढ़-मदारिया-मारवाड़ सहित 2000 किलोमीटर से अधिक के नई लाइन व दोहरीकरण के सर्वे प्रगति पर है।

## संपादकीय

# चलती ट्रेन पर हुड़दंग नहीं, जिम्मेदारी निभाएं

होली रंगों और खुशियों का पर्व है। यह उत्सव प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन कुछ लोग इस आनंद के अवसर को हुड़दंग और अव्यवस्था में बदल देते हैं। विशेष रूप से चलती ट्रेनों पर पानी के गुब्बारे फेंकना, रंग डालना या पत्थर मारना न केवल अनुचित है, बल्कि यह खतरनाक भी है। चलती ट्रेन पर गुब्बारे या अन्य वस्तुएं फेंकने से यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती है। खिड़की के पास बैठे बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं अचानक हमले से घबरा जाते हैं। कई बार शीशे टूटने की घटनाएं भी सामने आती हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। यह केवल शरारत नहीं, बल्कि कानूनन अपराध है।

रेलवे हमारी अपनी संपत्ति है। यह देश की जीवनरेखा है, जो करोड़ों लोगों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। ट्रेनों, पटरियों और स्टेशनों को नुकसान पहुंचाना दरअसल देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। त्योहार के नाम पर यदि हम सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, तो इसका खामियाजा अंततः आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। होली का असली आनंद दूसरों की खुशी में है, न कि उन्हें परेशान करने में। हमें यह समझना होगा कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्री भी किसी जरूरी काम से यात्रा कर रहे होते हैं, कोई परीक्षा देने जा रहा है, कोई इलाज के लिए, तो कोई अपने परिवार से मिलने। उनकी सुरक्षा और सुविधा हमारी जिम्मेदारी है।

जब हम रेलवे को अपनी संपत्ति मानकर उसका संरक्षण करेंगे, तभी देश सच्चे अर्थों में आगे बढ़ेगा। जिम्मेदार नागरिक बनकर ही हम एक सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं।

**रेल समाचार ब्यूरो की ओर से आप सभी पाठकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।**

**प्रधान संपादक**

# महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे ने परिचालन नियंत्रण केंद्र- डीएफसी का किया निरीक्षण और एआई के प्रयोग कर क्रू बुकिंग के दिए निर्देश

सूत्र/रे.स.ब्यू- श्री नरेश पाल सिंह महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे ने दिनांक 11.02.2026 को डीएफसीसीआईएल के परिचालन नियंत्रण केन्द्र प्रयागराज का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे के रूप में कार्यभार संभालने के बाद डीएफसीसीआईएल में यह उनका पहला निरीक्षण रहा। यह निरीक्षण उत्तर मध्य रेलवे और डीएफसीसी-आईएल के बीच नए कनेक्शन जैसे चुनार से न्यू डगमगपुर, भीमसेन से न्यू भीमसेन, एकदिल से न्यू एकदिल, मख्खनपुर से न्यू मख्खनपुर, टूंडला से न्यू टूंडला, तथा भारतीय रेलवे में चलने वाली सभी मालगाड़ियों को ईडीएफसी में स्थानांतरित करने के उद्देश्य के क्रम में किया गया ।

माल के त्वरित एवं समयबद्ध परिवहन के लिए बजट 2026 में डानकुनी-सूरत डीएफसी के अंतर्गत नए कारीडोर के फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे ने सभी नियंत्रण अधिकारियों के साथ बातचीत की, परिचालन नियंत्रण केंद्र (ओ सी सी) में उपयोग में लाई जा रही सभी तकनीकी जानकारियों की समीक्षा की तथा सराहना की। महाप्रबंधक मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम और हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर मशीन के उपयोग और उसके परिणामों से प्रभावित और संतुष्ट थे।

अपने संबोधन के दौरान महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे ने ईडीएफसी में किए जा रहे ट्रेन संचालन की सराहना की तथा कृत्रिम बुद्धिमता(एआई) का प्रयोग कर क्रू बुकिंग के बारे मे निर्देश दिए, साथ ही एसेट विफलता को कम करने के लिए सभी विभागों को आपस मे सहयोग बनाने के दिशा निर्देश दिए। वर्तमान समय मे ईडीएफसी अपने उच्चतम क्षमता का उपयोग कर रही है। महाप्रबंधक ने सभी अधिकारियों को सलाह दी है कि वे ट्रेन संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी साथ लगे हुए जोनों जैसे कि पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे , उत्तरी रेलवे के साथ समन्वय करें।

माघ मेला के दौरान जनवरी के महीने में औसतन 455 गाड़ियों का संचालन किया गया । दिनांक 29.01.2026 को न्यू पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से अधिकतम (अप दिशा में 101) और दिनांक 08.02.2026 को न्यू कानपुर से अधिकतम (डाउन दिशा में 94) मालगाड़ियों का संचालन ईडीएफसी पर किये जाने की महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे ने सराहना की ।

महाप्रबंधक ने सलाह दी कि उत्तर रेलवे , उत्तर मध्य रेलवे और ईसीआर से आने वाली ट्रेनों की संख्या में वृद्धि के साथ ईडीएफसी में लॉंगर लूप की की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे ने इंटरचेंज डिटेंशन से बचने के लिए सिंगल लाइन कनेक्शन को डबल लाइन करने पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। महाप्रबंधक ने कार्य के दायरे को अंतिम रूप देने, जैसे न्यू पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन वातानुकूलित रनिंग रूम इसी माह , और न्यू खुर्जा में बनाए जा रहे वातानुकूलित रनिंग रूम की जून माह के अंत तक अंतिम रूप देने को कहा। न्यू कानपुर जंक्शन के वातानुकूलित रनिंग रूम की क्षमता का विस्तार करने की चर्चा की । आने वाले समय में लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर इन रनिंग रूम में उचित आराम कर सकेंगे और बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें मनोरंजन कक्ष आदि शामिल हैं।

महाप्रबंधक ने भारतीय रेलवे में कोचिंग ट्रेनों की बेहतर समयबद्धता की भी प्रशंसा की और ईडीएफसी के प्रयास की सराहना की। यह ईडीएफसी में अधिकतम मालगाड़ियों की आवाजाही से कोचिंग ट्रेनों की बेहतर समयबद्धता को दर्शाता है ।

महाप्रबंधक ने बैठक के समापन पर कहा कि आने वाले महीनों में ईडीएफसी में मालगाड़ियों की संख्या में और वृद्धि होगी तथा उन्होंने नई उपलब्धियां हासिल करने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

# मण्डल रेल प्रबंधक/प्रयागराज ने किया टूंडला-इटावा खंड का निरीक्षण

सूत्र/रे.स.ब्यू- दिनांक 11 फरवरी, 2026 को मंडल रेल प्रबंधक/प्रयागराज, श्री रजनीश अग्रवाल द्वारा यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं परिचालन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए टूंडला-इटावा रेल खंड का निरीक्षण यान से व्यापक विंडो-ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। इस विंडो-ट्रेलिंग निरीक्षण के दौरान दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संरक्षा से जुड़े सभी मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया ।

उल्लेखनीय है कि विंडो-ट्रेलिंग निरीक्षण भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी निरीक्षण माध्यम है, जिसके अंतर्गत चलती ट्रेन/निरीक्षण यान की खिड़की से रेल पथ तथा उससे जुड़े प्रतिष्ठानों जैसे सिग्नल, ओएचई, प्लेटफॉर्म एवं समपार फाटकों की स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है । इस दौरान स्टेशनों की स्वच्छता, यात्री सुविधाएं, परिचालन की समग्र स्थिति, प्वाइंट एवं क्रॉसिंग पर सवारी की गुणवत्ता, ट्रैक ज्योमेट्री इंडेक्स (TGI), ओएचई की स्थिति, समपार फाटकों की सुरक्षा, बैलास्ट की स्थिति, सिग्नल श्यता तथा सिग्नल बॉक्स की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मानकों की गहन समीक्षा की जाती है । 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत विकसित किए जा रहे इटावा जंक्शन एवं शिकोहाबाद जंक्शन के निर्माणाधीन स्टेशन भवन के सिविल कार्यों, संरचनात्मक प्रगति, यात्री सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों तथा निर्माण गुणवत्ता का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, प्रवेश-निकास द्वार, फुट ओवर ब्रिज, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएँ, शौचालय, जल निकासी व्यवस्था तथा अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की। साथ ही स्टेशन परिसर के सौंदर्यीकरण, स्थानीय संस्कृति एवं विरासत को प्रदर्शित करने वाले डिजाइन तत्वों पर भी विशेष ध्यान दिया । स्टेशन निरीक्षण के दौरान यात्रियों से भी संवाद स्थापित किया गया तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना गया । निरीक्षण के दौरान इटावा स्टेशन पर मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की ।

मण्डल रेल प्रबन्धक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएँ तथा गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्टेशन उपलब्ध कराना है, जिसमें विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं का भी समावेश हो । स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए संकेतक बोर्ड, डिजिटल सूचना प्रणाली, स्वच्छता व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था तथा पार्किंग सुविधा को प्रभावी ढंग से विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कार्यो के चरणबद्ध निष्पादन की समीक्षा की और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी दिए ।

निरीक्षण के समापन पर मॉडल रेल प्रबंधक ने कहा कि रेलवे का उद्देश्य केवल सुरक्षित संचालन ही नहीं, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी कमियों को शीघ्र दूर करने एवं निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए ।

# उत्तर मध्य रेलवे ने 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025' में गाड़े सफलता के झंडे, महाप्रबंधक ने रेल मंत्री से प्राप्त कीं दो दक्षता शील्ड

सूत्र/रे.स.ब्यू-उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025' समारोह के दौरान शीर्ष संगठनात्मक और व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारतीय रेलवे के इस सर्वोच्च वार्षिक सम्मान को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदान किया गया।

उत्तर मध्य रेलवे के लिए यह एक गौरवशाली क्षण था जब महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने पीसीएसटीई (PCSTE) श्री सत्येंद्र कुमार के साथ दो प्रतिष्ठित संगठनात्मक ट्राफियां प्राप्त कीं: टेलीकम्युनिकेशन एफिशिएंसी शील्ड (दूरसंचार दक्षता शील्ड) और सिग्नल एफिशिएंसी शील्ड। ये पुरस्कार नेटवर्क में उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और अत्याधुनिक संचार तकनीक को लागू करने में उत्तर मध्य रेलवे के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं।

### उत्कृष्टता के व्यक्तिगत कीर्तिमान

समारोह में उत्तर मध्य रेलवे के उन पांच कर्मियों के असाधारण योगदान को भी सम्मानित किया गया, जिनके समर्पण ने भारतीय रेलवे के लिए नए मानक स्थापित किए हैं:

**श्री आशुतोष शर्मा** (Dy FA & CAO): उन्हें महाकुंभ परिचालन के दौरान उनके कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। लगभग 50 करोड़ के कार्यों की सूक्ष्म जांच के माध्यम से उन्होंने करीब 7 करोड़ की वसूली सुनिश्चित की, जो उनकी वित्तीय सत्यनिष्ठा को दर्शाता है।

**श्री कुश गुप्ता** (Dy- CSTE): उन्हें ''रिकॉर्ड समय में परियोजनाओं को पूरा करने'' की श्रेणी के तहत मान्यता दी गई। उनके नेतृत्व में महत्वपूर्ण सिग्नल और टेलीकॉम परियोजनाओं को समय से पहले पूरा किया गया, जिससे जोन की परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई।

**श्री धनंजय कुमार सिंह** (Sr- DME/ Prayagraj): महाकुंभ के दौरान उनकी रणनीतिक योजना के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने झांसी, ग्वालियर और आगरा सहित कई स्थानों पर 150 से अधिक रेक के रखरखाव का प्रबंधन किया। उनकी ''जीरो-डिटैचमेंट'' रणनीति ने सुनिश्चित किया कि आयोजन के दौरान कोई भी कोच रखरखाव के लिए हटाया न जाए।

**सुश्री सुष्मिता** (Sr- ALP/Prayagraj): बनारस-आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के दौरान उनकी सूझबूझ के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। एक रोड-ट्रैफिक इंटरफेस पर देरी से मिले ग्रीन सिग्नल को भांपते हुए उन्होंने तत्काल आपातकालीन कार्रवाई की और एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया।

**श्री पर्वत जी (ट्रैकमैन/झाँसी)**: रेलवे के इस ''फुट सोल्जर'' को उनकी सतर्कता के लिए सम्मानित किया गया। नियमित गश्त के दौरान उन्होंने पटरियों की असुरक्षित स्थिति का पता लगाया और तुरंत प्रशासन को सतर्क किया, जिससे संभावित हादसा रुक गया।

निष्कर्ष अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार रेलवे कर्मचारियों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष उत्तर मध्य रेलवे की उपलब्धियां जोन की पेशेवर संस्कृति और राष्ट्र को सुरक्षित व तेज परिवहन अनुभव प्रदान करने के इसके मिशन का प्रमाण हैं।

# बजट 2026 में ‘आयुष’ भारत के समेकित स्वास्थ्य देखभाल के केंद्र में

सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्रीय बजट 2026-27 में आयुष पारितंत्र सुदृढ़ करने की घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने इन्हें भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बड़ा समर्थन बताया।

आयुष मंत्री ने बजट को दूरदर्शी और भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि ये उपाय समग्र, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन्नत बनाने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, जिनमें आयुष एकीकृत स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्तंभ है।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में, आयुष में शिक्षा, अनुसंधान, गुणवत्ता आश्वासन, वैश्विक नेतृत्व, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पर्यटन और कुशल कार्यबल बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। ये उपाय पारंपरिक चिकित्सा को निवारक स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक विकास और कल्याण में वैश्विक नेतृत्व के मुख्य चालक के रूप में स्थापित करने की भारत की आकांक्षा मजबूत करते हैं। बजट में ऐतिहासिक रूप से उच्च-गुणवत्तापूर्ण स्नातक और परास्नातक शिक्षा, उच्च अनुसंधान और आधुनिक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं विस्तारित करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों की सफलता के आधार पर इन संस्थानों से देश भर में शैक्षणिक मानक और समुन्नत होने तथा साक्ष्य-आधारित समेकित स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ होने की संभावना है।

बजट में आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उच्च प्रमाणन मानकों के अनुरूप उन्नत बनाने का भी प्रस्ताव है। इस कदम से उत्पाद गुणवत्ता, उपभोक्ता विश्वास और

निर्यात तैयारी बढ़ेगी, साथ ही औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों और प्रसंस्करण और विनिर्माण में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी मदद मिलेगी।

भारत के वैश्विक नेतृत्व को और सुदृढ़ बनाते हुए, जामनगर स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र को समुन्नत बनाया जाएगा, ताकि अनुसंधान सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और नीतिगत संवाद को सघन बनाया जा सके और भारत पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप स्थापित हो।

आर्थिक समेकन के महत्वपूर्ण कदम के तौर पर प्रस्तावित क्षेत्रीय उन्नत चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में पांच आयुष केंद्र स्थापित किये जाएंगे। इससे एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल स्थानक बनेंगे जो उन्नत स्वास्थ्य चिकित्सा को पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और पुनर्वास (शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सामान्य जीवन में वापस लाना) में मदद करेंगे। इस पहल से आयुष चिकित्सक, थेरेपिस्ट (प्रशिक्षित चिकित्सा सहायता पेशेवर), योग प्रशिक्षक और संबंधित पेशेवरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एनएसक्यूएफ केयरगिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग और स्वास्थ्य देखभाल शामिल करने से - अगले साल डेढ़ लाख केयरगिवर तैयार किये जा सकेंगे, बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल अर्थव्यवस्था में आयुष से जुड़े कौशल को मुख्यधारा में लाया जाएगा और अग्रिम और वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

श्री जाधव ने कहा कि पिछले एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष में अभूतपूर्व संस्थागत विकास, वैश्विक पहचान, डिजिटल विस्तार और अनुसंधान में प्रगति हुई है। यह बजट उसी मजबूत नींव पर आधारित है, जिसमें विस्तार से आगे बढ़कर एकीकरण, गुणवत्ता वृद्धि और वैश्विक एकीकरण की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णायक क्षण है जहां पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पूरक के रूप में नहीं, बल्कि भारत के स्वास्थ्य देखभाल भविष्य के अभिन्न अंग के रूप में देखा जा रहा है।

श्री जाधव ने बजट घोषणाओं के व्यापक आर्थिक प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये स्वास्थ्य नीति को ग्रामीण आजीविका, निर्यात वृद्धि, युवा रोजगार और उद्यमिता से जोड़ती हैं - जिससे भारत साक्ष्य-आधारित समग्र स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

केंद्रीय आयुष मंत्री ने अटूट समर्थन और दूरदर्शी ष्टिकोण के लिए माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह बजट स्वस्थ, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर सम्मानित भारत के एकीकृत स्वास्थ्य सेवा को संस्थागत बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है।

# प्राकृतिक चिकित्सा-2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने “योग संयोजन'' के माध्यम से एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पर प्रकाश डाला

सूत्र/रे.स.ब्यू- दिनांक 5-6 फरवरी 2026 को आयोजित प्राकृतिक चिकित्सा-2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रख्यात विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएन-आईवाई) और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

सम्मेलन का मुख्य विषय ‘‘एक मजबूत और स्वस्थ आपके लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा‘‘ था, जबकि उप-विषय ‘‘समयोग“ का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुष प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए एक साझा ज्ञान आधार बनाना है।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय श्री प्रतापराव जाधव ने एक वर्चुअल संदेश में कहा कि आयुष पद्धतियों के एकीकरण से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है। उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री मोनालिसा डैश ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अभूतपूर्व सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसे 2026 में 190 देशों में मनाया गया। भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन के रूप में ‘‘वसुधैव कुटुंबकम‘‘ का उल्लेख करते हुए, उन्होंने एक सतत, एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया।

”योग संयोग“ शीर्षक वाले अकादमिक खंड का केंद्र बिंदु ”योग अनुसंधान: अतीत, वर्तमान और भविष्य“ था। सत्रों में योग के वैज्ञानिक विकास पर विचार-विमर्श करने के लिए अग्रणी विशेषज्ञ एक साथ आए।

प्रथम सत्र की अध्यक्षता एमडीएनआईवाई के निदेशक प्रो. (डॉ.) काशीनाथ समागंडी ने की। इसमें महाराष्ट्र के नासिक स्थित योग विद्या गुरुकुल के निदेशक डॉ. विश्वास मंडलिक ने योग निद्रा को मनोचिकित्सा के रूप में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से मोटापा, रीढ़ की हड्डी संबंधी विकार और अनिद्रा जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में योग निद्रा के लाभों को समझाया।

कैवल्यधाम में वैज्ञानिक अनुसंधान के सहायक निदेशक डॉ. सतीश डी. पाठक ने कैवल्यधाम में किए गए संबोधन में अपने योग अनुसंधान निष्कर्षों के बारे में बताते हुए कहा कि मधुमेह एक तेजी से बढ़ता जीवनशैली विकार है जिसे प्रारंभिक निदान, संतुलित जीवनशैली प्रथाओं, योग और प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के निदेशक (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) और पुणे स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) के अतिरिक्त प्रभारी निदेशक श्री अमरेंद्र सिंह उपस्थित थे। उन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा की वैज्ञानिक नींव को मजबूत करने और उनकी व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करने में अनुसंधान, शिक्षा और जन जागरूकता की भूमिका पर प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में नई दिल्ली स्थित एम्स के शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉ. रमेश बिजलानी ने स्वास्थ्य सेवा के लिए योग के प्रभावशाली शोध पर एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने योग की विश्वसनीयता और उपयोगिता को और मजबूत करने के लिए निरंतर, ठोस और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित शोध की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. जगदीश प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित तीसरे सत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवनशैली संबंधी विकारों, योग चिकित्सा में प्रगति और ध्यान और नींद के तंत्रिका-शारीरिक पहलुओं पर शोध प्रस्तुतियाँ शामिल थीं, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ योग के बढ़ते एकीकरण को दर्शाती हैं। समापन सत्र में, प्रो. (डॉ.) काशीनाथ समागंडी ने सम्मेलन को सफल बनाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग के लिए सभी प्रतिभागियों और वक्ताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। पूर्ण सत्रों के दौरान हुई चर्चाओं में साक्ष्य-आधारित पद्धतियों, अंतर्विषयक सहयोग और स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संरचित एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

कुल मिलाकर, प्राकृतिक चिकित्सा-2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन ने ज्ञान के आदान-प्रदान, नीति संवाद और सहयोगात्मक जुड़ाव को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया, जो एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देने के भारत सरकार के दृष्टिकोण की पुष्टि की।

# केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने जेजे अस्पताल में नवीनीकृत यूनानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और मुंबई में यूनानी दिवस 2026 समारोह की अध्यक्षता की

## नवाचार और साक्ष्य यूनानी चिकित्सा के आगामी युग को आकार देने वाले दो स्तंभ हैं : श्री प्रतापराव जाधव

सूत्र/रे.स.ब्यू- केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने जेजे अस्पताल परिसर में स्थित क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आरआरआईएम), मुंबई के नवीनीकृत सह-स्थान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने मुंबई में यूनानी दिवस 2026 समारोह तथा ‘‘यूनानी चिकित्सा पद्धति में नवाचार और साक्ष्य‘‘ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआर-एम) की ओर से किया जा रहा है।

1984 में स्थापित नवीनीकृत आरआरआईएम सह केन्द्र को लगभग 3.84 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत किया गया है ताकि एकीकृत परिवेश में नैदानिक सेवाओं, अनुसंधान सुविधाओं और रोगी देखभाल को बेहतर बनाया जा सके। इस उन्नयन का उद्देश्य ऐतिहासिक जेजे अस्पताल परिसर में यूनानी चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करना और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के सहयोग से साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि जेजे अस्पताल में यूनानी अनुसंधान केंद्र का उन्नयन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक, रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा ढांचे का एक अनिवार्य स्तंभ बनाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यूनानी और पारंपरिक चिकित्सा को एक ही छत के नीचे लाकर, नवीनीकृत सह-स्थान केंद्र रोगियों को वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रमाणों द्वारा समर्थित सुरक्षित, प्रभावी और समग्र देखभाल प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल आयुष प्रणालियों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने और सभी के लिए समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण को और मजबूत करेगी।

श्री जाधव ने नवाचार और अनुसंधान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा, ”यूनानी चिकित्सा एक समय-परीक्षित प्रणाली है जो समदृद्ध नैदानिक अनुभव पर आधारित है, लेकिन इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वैज्ञानिक प्रमाणों को कितनी प्रभावी ढंग से उत्पन्न और विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।“ उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मुंबई स्थित सीसीआरएम और आरआरआईएम जैसे संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण और प्रयोगात्मक अध्ययनों में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए ताकि यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

श्री जाधव ने राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय का उल्लेख करते हुए कहा, ”नवाचार और प्रमाण, यूनानी चिकित्सा के आगामी युग को आकार देने वाले दो स्तंभ हैं। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक यूनानी औषधि, प्रक्रिया और चिकित्सीय प्रोटोक ल ठोस आंकड़ों द्वारा समर्थित हो और गुणवत्ता एवं सुरक्षा के वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।“ उन्होंने शोधकर्ताओं से आग्रह किया कि वे यूनानी अवधारणाओं और चिकित्सा पद्धतियों की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देने के लिए जीनोमिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत निदान सहित आधुनिक उपकरणों का उपयोग करें।

केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री ने एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के सफल मॉडल को प्रदर्शित करने में महाराष्ट्र, मुंबई के प्रमुख चिकित्सा संस-थानों और यूनानी चिकित्सा केंद्रों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, ”मुंबई के आरआर-आईएम जैसे केंद्रों को मजबूत करके और अग्रणी अस्पतालों तथा विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी स्थापित करके, हम एक ऐसा सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं जहां यूनानी चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य, निवारक देखभाल और दीर्घकालिक रोगों के प्रबंधन में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है।“

महाराष्ट्र सरकार में सहकारिता मंत्री श्री बाबासाहेब पाटिल ने मुंबई में यूनानी दिवस के आयोजन और जेजे अस्पताल में नवीनीकृत यूनानी सह-चिकित्सा सुविधा के उद्घाटन की सराहना करते हुए इसे किफायती और जन-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने यूनानी चिकित्सा से अपने स्वयं के सकारात्मक उपचार के अनुभव को याद करते हुए कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का जब अनुशासन और रोगी के सहयोग से पालन किया जाता है, तो विशेषकर गरीब और वंचित समुदायों के लिए दीर्घकालिक और कठिन उपचार वाली बीमारियों में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महाराष्ट्र बुनियादी ढांचे में सुधार, कॉलेजों और अस्पतालों को मजबूत बनाने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पहुंच सुनिश्चित करके यूनानी चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के विकास में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘स्वास्थ्य ही सच्चा धन है‘‘, और नागरिकों से आयुष प्रणालियों द्वारा प्रचारित निवारक और समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो और लोग स्वस्थ एवं अधिक उत्पादक जीवन जी सकें। श्री पाटिल ने कहा, ‘‘यूनानी चिकित्सा विशेष रूप से आम लोगों के लिए किफायती और प्रभावी उपचार प्रदान करती है, और महाराष्ट्र बेहतर सुविधाओं और व्यापक पहुंच के माध्यम से इसके विस्तार में सहयोग देना जारी रखेगा।‘‘

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इस बात का उल्लेख किया कि दसवें यूनानी दिवस समारोह और ‘‘यूनानी चिकित्सा में नवाचार और साक्ष्य‘‘ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले दशक में यूनानी चिकित्सा के असाधारण विकास को दर्शाते हैं, विशेष रूप से अनुसंधान, रोगी देखभाल और संस्थागत विकास के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि लक्षित नीतिगत समर्थन, बजट आवंटन में वृद्धि और मंत्रालय स्तर पर निरंतर नेतृत्व के माध्यम से, सीसीआरएम और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत आने वाले यूनानी संस्थानों ने अपनी सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। इसकी हाल के वर्षों में रोगियों की संख्या, प्रकाशनों और मान्यता प्राप्त सुविधाओं में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आयुष मंत्रालय यूनानी शिक्षा, अनुसंधान, नैदानिक प्रशिक्षण और उपचारात्मक समाधानों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने यूनानी चिकित्सा में प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए डब्ल्यूएचओ के मानक दस्तावेजों के प्रकाशन, आईसीडी-11 के पारंपरिक चिकित्सा अध्याय में यूनानी रुग्णता कोडों को शामिल करने और स्वास्थ्य समाधानों के वर्गीकरण पर चल रहे कार्यों जैसी प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये विकास न केवल आयुष प्रणालियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होंगे, बल्कि विश्वभर के देशों को अधिक विश्वास और मानकीकरण के साथ यूनानी चिकित्सा को अपनाने में भी सक्षम बनाएंगे।

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) की अध्यक्ष डॉ. मनीषा वी. कोठेकर ने इस बात पर जोर दिया कि यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद, सिद्ध और सोवा-रिग्पा के साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में ‘‘विविधता में एकता‘‘ की साझा भावना का प्रतिनिधित्व करती है। यहां विभिन्न चिकित्सा परंपराएं स्वास्थ्य और मानव शरीर को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखती हैं, लेकिन अंततः समाज के कल्याण को सुनिश्चित करने के एक ही लक्ष्य की ओर काम करती हैं। उन्होंने जेजे अस्पताल में यूनानी सह-स्थान सुविधा के नवीनीकरण और उद्घाटन की सराहना की और भारतीय पारंपरिक ज्ञान के मूल सिद्धांतों में निहित रहते हुए यूनानी बुनियादी ढांचे, शिक्षा, विनिर्माण और अनुसधान को मजबूत करने के लिए सीसीआरएम, आरआरआईएम और आयोजकों को बधाई दी।

उद्घाटन समारोह के दौरान कई संस्थागत पहलों का अनावरण किया गया, जिनमें यूनानी चिकित्सा पर एक वीडियो टीजर, सीसीआरएम प्रकाशनों और सम्मेलन स्मारिका का विमोचन, सीसीआरएम के सहयोगी वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ, एक अंतरराष्ट्रीय और आठ राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान और मिजाज-ए-इंसान (मानव स्वभाव) के आकलन के लिए एक प्रश्नावली का प्रस्तुतीकरण शामिल है। मुंबई स्थित आरआरआईएम की जैव रसायन एवं विंति विज्ञान प्रयोगशाला को भी एनएबीएल प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिससे यूनानी अनुसंधान में गुणवत्ता आश्वासन को और मजबूती मिली।

## Historic Milestone on Darjeeling Himalayan Railway as First Female TTE Appointed in 145 Years

**Source/RSB-**Marking a significant moment in its 145-year legacy, the Darjeeling Himalayan Railway has appointed Sarita Yolmo as its first woman Travelling Ticket Examiner. She initially worked at the Railway Press before qualifying as a TTE in New Jalpaiguri. Currently, she is deployed on heritage tourism services operating along the 78 km New Jalpaiguri–Darjeeling route. Her appointment reflects a strong step towards women empowerment, highlighting growing opportunities and greater representation of women in the railway sector.

## SHRI SAHARSH BAJPAI TAKES OVER AS PRINCIPAL CHIEF PERSONNEL OFFICER OF WR

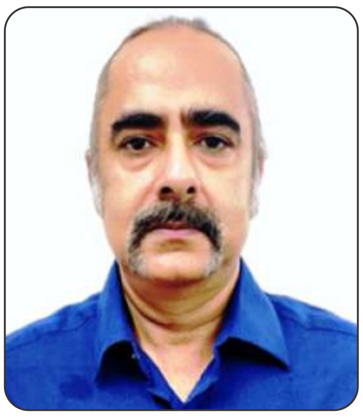

**Source/WR-** Shri Saharsh Bajpai, an officer of the 1999 batch of Indian Railway Personnel Service (IRPS), has assumed charge as the Principal Chief Personnel Officer (PCPO) of Western Railway on Tuesday, 03rd February, 2026. Prior to this assign-ment, Shri Bajpai has held several important administrative and personnel-related positions on Indian Railways. He has served in key roles across North Eastern Railway, Central Railway and Maharashtra Metro. Prominent among these are Sr. Divisional Personnel Officer, Pune; Chairman, Railway Recruitment Cell, Central Railway; Deputy Chief Personnel Officer; Additional Divisional Railway Manager, Pune; General Manager (HR), Maha Metro; and Principal Chief Personnel Officer, Central Railway. Shri Bajpai holds a Master of Public Administration (MPA) degree from the National University of Singapore. He has extensive experience in the field of Human Resource Management, personnel administration and policy formulation. Throughout his career, he has been actively associated with strengthening the Human Resource Management System (HRMS), improving personnel administration & promoting employee-centric governance practices.

His wide exposure at both field units and headquarters level has enabled him to adopt a balanced and pragmatic approach towards personnel management. Shri Bajpai has also undergone various international training programmes at INSEAD, Singapore; ICLIF, Malaysia; KOTI, South Korea; and SWJTU, China.

## Konkan Railway Ensures Passenger Safety Through Vigilant On-Board Checks

Source/KR- Konkan Railway continues to prioritise the safety and security of passengers through constant vigilance. On 09.02.2026, during routine ticket checking in Train No. 22150 Pune–Ernakulam Superfast Express, an unclaimed bag was noticed in B1 Coach.

The bag was promptly secured and handed over to the Railway Protection Force for further action. The bag contained cash amounting to ₹4,933/-, a wallet, Aadhaar card, ATM and credit cards, keys, charger, data cable, earphones and other documents.

Konkan Railway appeals to passengers to remain alert and report any unattended belongings to railway staff to help maintain a safe & secure travel environment.

## CONCOR Signs MoU to Form Bharat Container Shipping Line

**Source/RSB-** Container Corporation of India Ltd. (CONCOR) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with key maritime stakeholders for the formation of the proposed joint venture, Bharat Container Shipping Line (BCSL).The MoU was signed on 3 February 2026 at New Delhi with the Shipping Corporation of India (SCI), V.O. Chidambarnar Port Authority (VOCPA), Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA), Chennai Port Authority (CPA), and Sagarmala Finance Corporation Ltd. (SMFCL).The MoU signing took place in the august presence of Shri Ashwini Vaishnaw , Hon'ble Union Minister for Railways, and Shri Sarbananda Sonowal , Hon'ble Union Minister of Ports, Shipping and Waterways. The ceremony was also attended by Shri Shantanu Thakur , Hon'ble Union Minister of State for Ports, Shipping and Waterways. The proposed JV, BCSL, aims to acquire, own, lease, and operate container vessels, containers, and related assets for EXIM and coastal trade, enabling integrated end-to-end multimodal logistics solutions by leveraging the collective expertise of ports, shipping, rail, and maritime finance stakeholders.

## CMD, RVNL directs all stakeholders to ensure commissioning of the project in 2028.

### This project can be a game changer for the "Nation's development," says CMD RVNL

**Source/RSB-** Shri Saleem Ahmad, Chairman & Managing Director, Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), undertook a two-day visit to the Rishikesh– Karnapraygag New Broad Gauge Rail Link Project site on 2nd and 3rd February 2026, during which he conducted a comprehensive review of the project's progress, inspected critical construction sites, and interacted with key stakeholders and workforce engaged in this strategically important Himalayan rail corridor. The 125-km Rishikesh–Karnaprayag New Broad Gauge Rail Link Project, being executed by Navratna CPSU Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) for Indian Railways in Uttarakhand, is one of India's most ambitious and strategically important rail infrastructure initiatives in the Himalayan region. On the first day of his visit, the CMD chaired a marathon review meeting with senior project officials, engineers, contractors, and international and national tunnelling experts associated with various packages of the project. Detailed deliberations were held on construction progress, complex geological challenges, tunnelling milestones, safety measures, and time-bound execution. Shri Ahmad categorically directed that the project must be commissioned positively in 2028, without compromising on quality or safety. The CMD underscored that the Rishikesh–Karnaprayag Rail Project, is not only a landmark engineering initiative but also a transformational infrastructure corridor that will redefine mobility in the Garhwal Himalayan region by providing all-weather, landslide-resilient rail connectivity to remote hinterlands. During discussions, the possibility of developing road tunnels alongside railway tunnels was also explored, which could significantly enhance road connectivity, safety, and travel convenience for local population in the hilly terrain, thereby maximizing infrastructure utility. On second day of visit, Shri Ahmad also conducted on-site inspections of ongoing tunnelling works, bridges, & station locations, where he reviewed safety practices, construction quality, and environmental safeguards. He interacted with workers and technical teams at site and thanked workforce for their dedication and contribution in executing the project under extremely challenging Himalayan conditions. He emphasized that environmental impact caused during construction would be systematically mitigated through green area development and extensive plantation, ensuring a balance between infrastructure growth & ecological conservation.

## RailTel Secures ₹455 Crore Kavach Project from West Central Railway

**Source/RSB-**RailTel Corporation of India Ltd., a Navratna CPSE under the Ministry of Railways, has achieved a significant milestone in the area of railway safety and modernization by securing a major order of implementing KAVACH system covering 1067 RKM of Jabalpur division of West Central Railway. Kavach is India's Indigenous Automatic Train Protection (ATP) System. RailTel has project valued at ₹454.95 crore, for Survey, Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Trackside Kavach Systems across key routes of the Jabalpur Division of West Central Railway. The project will be implemented over important and high-density corridors covering 1067 RKM, including Itarsi – Manikpur Section, Mahdeiya – Bina Malkheri–Mahadeokheri, Entire Katni Complex, Bina Malkheri – Agasod Section, Satna – Rewa Section, Kaima – Sagma Section and Bansapahar – Ohan Section of Jabalpur division of West Central Railway. The scope includes installation of Kavach equipment at stations, level crossing gates and IBS locations, along with OFC works, erection of towers and

रेलटेल
RAILTEL

associated civil, track and electrical works under EPC mode. The entire work is planned to be completed within 960 days as per the EPC agreement. Kavach is Indian Railways' flagship Indigenous Automatic Train Protection system developed under the vision of Atmanirbhar Bharat. It is designed to prevent train collisions, over-speeding, and signal passing at danger (SPAD), thereby significantly enhancing passenger safety and operational reliability. RailTel is already working on 2 projects for deploying Kavach covering 1109 route kilometres track of East Central Railway. Shri Sanjai Kumar, Chairman & Managing Director, RailTel, said: "This prestigious Kavach order from West Central Railway is a proud moment for RailTel and a strong recognition of our capabilities in delivering critical railway safety infra-structure. Kavach is a transformational initiative for Indian Railways, and RailTel remains committed to supporting the national mission of safer, smarter and technology driven rail operations through indigenous solutions."

# Game-Changer for Northeast: 33.7 Km Twin-Tube Underwater Road & Rail Tunnel Gets Cabinet Nod

**Source/RSB-** The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved construction of 4-Lane Access-Controlled Greenfield connectivity from Gohpur on NH-15 to Numaligarh on 715 section including 15.79 Km. of Road cum Rail Tunnel under River Brahmaputra to be developed at a total capital cost of Rs.18,662 crore in Assam on Engineering procurement Construction (EPC).

Currently, connectivity between Numaligarh on NH715 and Gohpur on NH-15 is 240 Km. from the existing Kaliabhambhora road bridge near Silghat on NH-52 which takes 6 Hours passing through Numaligarh, Kaziranga National park and Biswanath Town. To address these challenges, the project is proposed to be developed as 4-Lane Access-Controlled Greenfield connectivity from Gohpur on NH-15 to Numaligarh with Road cum Rail tunnel below the river Brahmaputra river. This would be the first underwater Road cum Rail tunnel in India and 2nd in the world. The project will provide significant benefit to Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland and other North-Eastern States. This will enhance the efficiency of freight movement, reducing logistics cost and driving socio-economic growth in the region.

The project alignment integrates with 02 major National Highways (NH-15 and NH-715) and 02 Railway lines i.e. Rangia-Mukongselek Railway Section under Rangia Division of NFR on Gohpur Side and Furkating-Mariani loop line section under Tinsukia Division of NFR on Numaligarh side. The project providing seamless connectivity to key economic, social, and logistics nodes across Assam. Additionally, the project will enhance multi-modal integration by connecting with 11 Economic Nodes, 03 Social Nodes, 02 Tourist nodes and 08 Logistic Nodes, providing enhanced connectivity with 04 Major Railway Station, 02 Airport, and 2 inland water way thereby facilitating faster movement of goods and passe-ngers across the region.

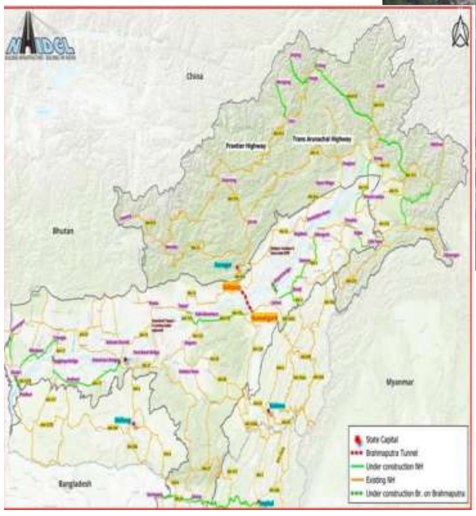


Upon completion, the project will play a pivotal role in strategic considerations, regional economic growth, strengthening connectivity between major economic centers and opening new avenues for trade and industrial development. The project will also generate approximately 80 Lakhs person days of direct and indirect employment, and will open new avenues of growth, development and prosperity in surrounding regions.

# ECoR Signs MoU with Bank of India for Comprehensive Banking Benefits to Employees

**Source/ECoR-** East Coast Railway today signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Bank of India (BoI) for providing an enhanced salary package with a wide range of banking and welfare benefits for its employees and their families.

The MoU signing ceremony was held at Sabhagriha, Rail Sadan, Bhubaneswar, in the presence of senior officers of East Coast Railway and repre-sentatives from Bank of India.

Under this MoU, Bank of India will extend several employee friendly benefits, including unlimited free ATM transactions, free demand drafts, concessional locker rentals, personal accident insurance, educational grants for wards, and health insurance coverage with premium options, aimed at ensuring greater financial security and convenience for railway employees. Speaking on the occasion, senior officials of East Coast Railway highlighted that the agreement reflects the organisation's continued commitment towards employee welfare and providing access to comprehensive financial services on attractive terms. Officials from Bank of India expressed their appreciation for the association with East Coast Railway and reiterated the Bank's commitment to delivering efficient, technology driven and employee centric banking solutions.

The MoU is expected to benefit a large number of serving railway employees by offering improved banking facilities and value added services under a single salary account framework.

# HBL Engineering Secures ₹575 Crore Order for KAVACH Systems

**Source/RSB-**HBL Engineering Limited has secured a significant order valued at ₹575 crore from Integral Coach Factory, Chennai. The contract covers the supply, testing, & commissioning of onboard KAVACH equipment (Version 4.0). The project is to be executed and completed within a period of 12 months, as per the agreed timeline.

The order marks a notable development for the company and reinforces its engagement in the supply of advanced onboard Railway systems.

# NCRTC Signs MoU with SPA Delhi to Strengthen Transit-Oriented Development Planning

**Source/RSB-**The National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the School of Planning and Architecture, New Delhi, to strengthen the planning and implementation of Transit Oriented Development (TOD) zones across all Namo Bharat corridors in the National Capital Region (NCR).

The MoU was formalised with the Center of Excellence in Urban Planning and Design at SPA Delhi & aims to enhance coordinated urban planning initiatives along the Namo Bharat network.

The agreement was signed in the presence of Shri Shalabh Goel, Managing Director, NCRTC, and Prof. Dr. V.K. Paul, Director, SPA Delhi.

# ISRO Begins Installation of Advanced Rail Track System at Second Launch Complex

**Source/RSB-** ISRO has begun inviting tenders for setting up a modern rail track system at its planned Second Launch Complex in Tamil Nadu. The track infrastructure will play a key role in transporting and positioning launch vehicles, especially for small rocket missions. The Satish Dhawan Space Centre is looking for contractors to design, supply, and install nearly 1,700 metres of heavy-duty tracks to ensure efficient movement of launch equipment within the facility.

# DELHI AEROCITY METRO STATION ON THE AIRPORT EXPRESS LINE TO BECOME A MAJOR INTERCHANGE HUB

Source/DMRC- The Delhi Aerocity Metro station on the Airport Express Line is all set to become a major interchange hub of the Delhi Metro network as it is being expanded to provide additional connectivity to the Tughlakabad – Aerocity Golden Line corridor, being constructed as part of Phase 4. Recently, approval has also been received for the extension of this corridor from Aerocity till Terminal 1 IGI Airport station (2.263 kms). In the future, the station will also have the provision of being turned into a triple interchange, as the National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) will have interchange facilities at Delhi Aerocity for its proposed corridor to Alwar. The new Delhi Aerocity Metro station will have platform-to-platform (for one side) as well as concourse-to-concourse paid area connectivity between the Airport Express Line and the Golden Line. The platform will come up at a depth of approximately 22 metres. The new station for the Golden Line will be significantly longer, at approximately 290 metres, to accommodate the interchange requirements. Generally, the length of an interchange station is about 260 metres. As per the alignment planned, the Golden Line and the proposed NCRTC corridor will cross each other almost diagonally. The necessary structural provisions for the construction of the NCRTC platform shall be kept in the station for its future integration. This new interchange facility will be a major connectivity boost for various areas of south Delhi, which will be connected by the Aerocity – Tughlakabad Metro corridor. Areas such as Tughlakabad, Ambedkar Nagar, Khanpur, etc will have quick access to all terminals of the Indira Gandhi International Airport.

Now with the approval to the extension of the Golden Line till Terminal 1 IGI Airport station of Magenta Line, passengers traveling from many south Delhi areas will have direct access to the Terminal 1 of the airport. Passengers from Terminal 1D will also be able to take the Airport Line from Aerocity through Metro by taking the Golden Line from Terminal 1 IGI Airport till Aerocity.

# WESTERN RAILWAY COMMISSIONS KAVACH 4.0 on VIRAR–SURAT–VADODARA SECTION

## *Train No. 20907 Dadar–Bhuj Sayajinagri Express becomes the first KAVACH equipped train to be run from Mumbai*

## Major Leap in Train Safety as Indigenous Protection System Goes Live for Passenger Services

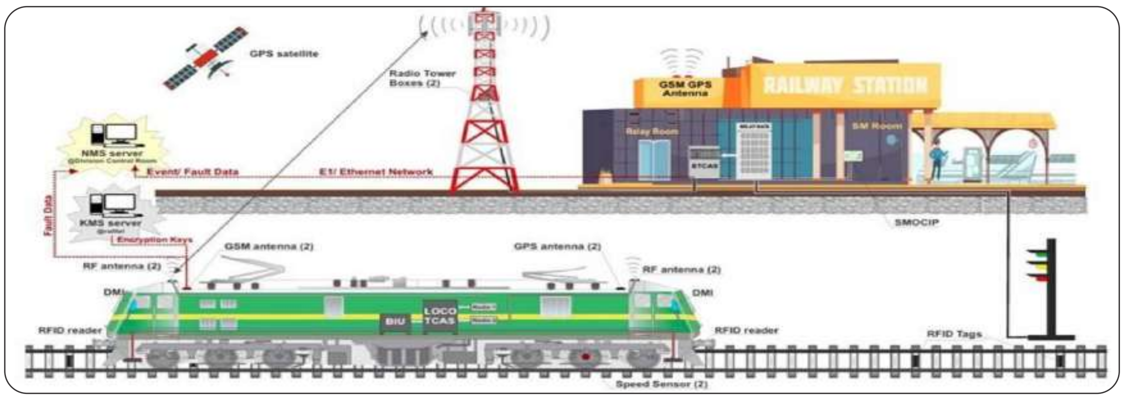


**Source/WR-** Reinforcing its unwavering commitment to passenger safety and operational excellence, Western Railway has commissioned KAVACH Version 4.0, the indigenously developed train protection system, for passenger services over the 344 km Virar–Surat–Vadodara section. on 30th January, 2026 a historic milestone was achieved with Train No. 20907, Dadar–Bhuj Sayajinagri Express, becoming the first KAVACH equipped train to run from Mumbai. This marks a significant step in the deployment of advanced safety technology over the Western Railway network.

According to a press release issued by the Chief Public Relations Officer of Western Railway, the KAVACH technology has been commissioned over 344 km of the Virar–Surat–Vadodara section. Over this corridor, KAVACH has been implemented covering 49 stations, supported by 57 radio communication towers, and about 700 km of optical fibre cable. KAVACH acts as an additional layer of safety to minimize risks arising from human error by preventing signal passing at danger, over-speeding and collisions, while also enhancing operational safety during adverse weather and low-visibility conditions through features such as auto-whistling at level crossings and in-cab signal aspect repetition.

Shri Vineet further stated that KAVACH technology, developed indigenously by Indian Railways, is a technologically advanced and cost-effective safety solution, symbolising Atmanirbhar Bharat in railway safety systems. In addition to the sections already commissioned, KAVACH works is progressing rapidly on several other sections of Western Railway covering 2667 route kilometres, at an approximate cost of ₹1435 crore. Apart from this, further works on 2476 route kilometres have been proposed for sanction, highlighting the scale and momentum of the programme. With phased execution underway, Western Railway is steadily moving towards extending KAVACH across its entire Broad Gauge network, reaffirming its long-term commitment to comprehensive rail safety enhancement. With sustained progress in deploying advanced safety systems across its network, Western Railway continues to move decisively towards building a safer, more reliable and future-ready railway system for the nation.

# MAJOR RAIL INFRASTRUCTURE BOOST FOR BENGAL, EXPANDS REGIONAL RAIL NETWORK

**SOURCE/RSB** Shri Ashwini Vaishnaw, Union Minister for Railways, Information & Broadcasting and Electronics & Information Technology, inaugurated the Siuri Road Over Bridge, dedicated the Kumarpur Road Over Bridge to the Nation and flagged off the new Asansol–Bokaro train service through Video Conferencing, along with Shri Suvendu Adhikari, Leader of the Opposition, West Bengal Legislative Assembly on Feb 8th.

Shri Anup Kumar Saha, Hon'ble MLA, Shri Jagannath Chattopadhyay and other dignitaries were also present at Siuri on this occasion. Speaking on the occasion, Shri Ashwini Vaishnaw stated that these projects mark a significant step towards strengthening rail infrastructure, enhancing safety and improving regional connectivity in West Bengal and adjoining areas. Hon'ble Railway Minister Shri Vaishnaw mentioned that this year a record budget allocation of Rs. 14,205 crores has been allocated for Railway in West Bengal which is more than 3 times than the average allocation during previous regime. He also mentioned that Railway Projects worth about Rs. 92,000 crore is continuing in West Bengal which will facilitate infrastructural transformation in this State. He mentioned that recently Hon'ble Prime Minister has initiated more than a dozen of new trains to facilitate enhancement in rail connectivity for the people of West Bengal. It is mentioned worthy that the first Vande Bharat Sleeper train started running from West Bengal and similarly first Amrit Bharat train was also started from West Bengal. This indicated the visionary initiative of 'Purvoday' taken by Hon'ble Prime Minister towards development of this region. Shri Vaishnaw, Hon'ble Railway Minister also mentioned that the first Bullet Train for West Bengal has been announced in this year's Rail Budget and this Bullet Train will start from Siliguri. At the same time, Hon'-ble Prime Minister has approvd for an East-West freight corridor connecting West Bengal with Gujarat. Another initiative is being taken for construction of an underground rail corridor at the Chicken-Neck part of North Bengal as a strategic step for safe and secured transportation.

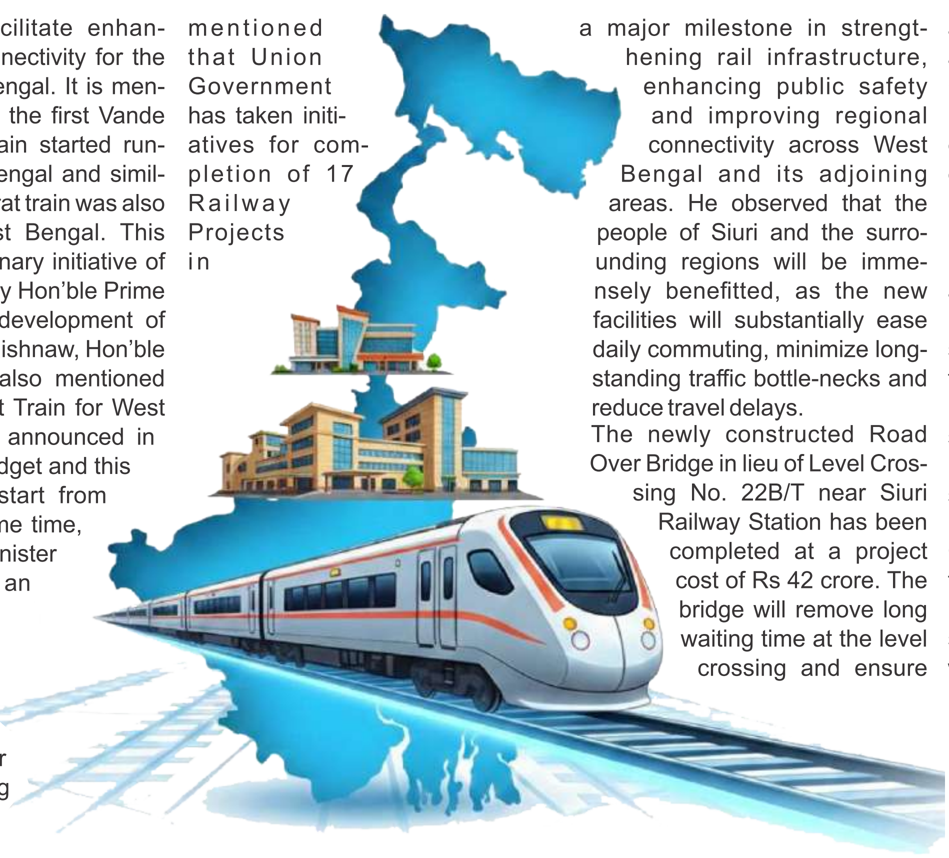

Shri Vaishnaw, Hon'ble Railway Minister said that though Union Government is taking all round initiatives for development of West Bengal but the lack of support and apathy of West Bengal Government is foiling those initiatives. He mentioned that Union Government has taken initiatives for completion of 17 Railway Projects in West Bengal for improving connectivity but the State Government should come forward to cooperate in completion of these projects. Shri Vaishnaw urged for cooperation from State Government for completion of Railway Projects for the betterment of the people of West Bengal. Speaking on the occasion at Siuri, Shri Suvendu Adhikari remarked that the inauguration of these projects represents a major milestone in strengthening rail infrastructure, enhancing public safety and improving regional connectivity across West Bengal and its adjoining areas. He observed that the people of Siuri and the surrounding regions will be immensely benefitted, as the new facilities will substantially ease daily commuting, minimize long-standing traffic bottle-necks and reduce travel delays.

The newly constructed Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 22B/T near Siuri Railway Station has been completed at a project cost of Rs 42 crore. The bridge will remove long waiting time at the level crossing and ensure faster, safer and smoother daily travel for residents of Siuri and adjoining areas. It will significantly enhance safety by eliminating a busy crossing, reduce congestion around Siuri station and improve mobility for students, workers and local commuters. The ROB will also enable uninterrupted movement of emergency vehicles during critical situations. Another major infrastructure addition is the Road Over Bridge at Kumarpur in lieu of Level Crossing No. 1Spl/E between Barachak & Hirapur Yard Line, constructed at a cost of Rs 55 crore. Located on the important GT Road corridor, it serves as a key link between Asansol city, large parts of Paschim Bardhaman district and Jharkhand. The bridge will facilitate faster and smoother movement of trade and traffic within the state and with neighbouring states, enhance safety on a heavily used route and reduce congestion around Asansol, improving daily commuting for local residents.

On the same occasion, the new train service between Asansol & Bokaro Steel City was flagged off, strengthening connectivity between two major steel hubs of the country. The service will benefit industrial workers, daily commuters and local residents. Running via Paschim Bardhaman and Purulia districts of West Bengal and Bokaro district of Jharkhand, the train will enhance both intra-state and inter-state mobility and support regional economic and social connectivity. In the inaugural run Asansol – Bokaro Steel City MEMU Inaugural Special was scheduled to leave Asansol at 17:00 hrs on 08.02.2026 to reach Bokaro Steel City at 21:45 hrs on the same day.

# Ministry of Railways Approves ₹421.41 Crore for Major Signaling Upgrades in Northern Railway

## New Electronic Interlocking Systems to be installed at 34 Stations across Delhi and Ambala Divisions to boost safety and efficiency

**Source/NR-** The Ministry of Railways has accorded its approval for two significant infrastructure projects under Northern Railway (NR), aimed at modernizing signaling systems and enhancing safety on High Density (HDN) and Highly Used Networks (HUN). The total sanctioned cost for these projects stands at ₹421.41 Crore.

The projects involve the Provision of Electronic Interlocking at stations where the indigenous "Kavach" automatic train protection system is sanctioned. This upgrade is critical for synchronizing modern signaling with the Kavach technology, ensuring safer train operations and higher throughput on busy routes.

The Hon'ble Minister of Railways has approved the following two itemized works:

**Delhi Division (DLI):** Provision of Electronic Interlocking at 21 stations on HDN/HUN routes. Cost: ₹292.24 Cr.

**Ambala Division (UMB):** Provision of Electronic Interlocking at 13 stations on HDN/HUN routes. Cost: ₹129.17 Cr.

These works have been sanctioned against the sub-umbrella work for Northern Railway (valued at ₹1,547 Cr), which falls under the larger umbrella approval in the Works, Machinery & Rolling Stock Programme (Pink Book) 2024-25.

The transition to Electronic Interlocking (EI) represents a significant leap in railway safety. Unlike traditional mechanical interlocking, EI utilizes computer-based systems to control signals and points, virtually eliminating the possibility of human error. By implementing EI on routes already sanctioned for Kavach, Northern Railway is creating a robust, fail-safe network capable of handling increased traffic density with maximum safety.

# MAJOR MILESTONE ACHIEVED BY AI-POWERED RAIL ROBOCOP "ASC ARJUN" AT VISAKHAPATNAM STATION

**Source/PIB-** Visakhapatnam Railway Station has achieved a significant milestone in strengthening passenger security with the successful real-time identification and apprehension of habitual offenders through the AI-powered Facial Recognition System (FRS) of Rail Robocop "ASC Arjun."

On the night of 02.02.2026 at about 20:10 hrs, Rail Robocop "ASC Arjun," deployed for surveillance and patrolling, detected a suspect by matching his facial image with the pre-loaded database of known criminals. The system immediately alerted the RPF CCTV Control Room, Visakhapatnam. Upon receipt of the alert, the on-duty CCTV staff Head Constable B.S. Narayana analysed the live CCTV feed and promptly informed the on-duty officer Sub Inspector V. Keerthi Reddy along with the Crime Prevention Detention Squad (CPDS) team of Waltair Division, who were present at the station. Acting swiftly on the alert, the team conducted a coordinated check and successfully apprehended a habitual offender, Hadapa Shiva (39 years) and his associate G. Bhangaru.

Both individuals failed to produce any valid journey tickets and were brought to the RPF Post, Visakhapatnam for further action. Verification of their antecedents revealed that both persons are hardcore habitual offenders with extensive criminal histories registered at Rayagada Police Station, involving multiple serious offences such as theft, robbery, dacoity, assault, and arms-related cases over several years. The apprehension was immediately informed to GRP Visakhapatnam, and further joint interrogation was conducted by RPF, GRP and their teams. After detailed enquiry, it was concluded that the suspects had entered the station area without valid authority and were detected at the entry stage itself by the AI-enabled Facial Recognition System of Rail Robocop "ASC Arjun."

As both offenders were found travelling without tickets, they were dealt with under the provisions of the Indian Railways Act, 1989 (Amended 2003). The matter was also intimated to Rayagada Police for further necessary action. Appraising the achievement of Rail Robocop ASC Arjun, the General Manager, East Coast Railway, Shri Parmeshwar Funkwal, said that the incident proved to be an effective technological intervention in enhancing passenger security. The Robocop ASC Arjun at Visakhapatnam Railway station, played a significant role in identifying and recognizing habitual offenders by leveraging advanced surveillance and artificial intelligence–based analytics, thereby assisting railway security agencies in timely action. Encouraged by the positive results at Visakhapatnam Railway Station, East Coast Railway will continue to explore and expand the use of such advanced security solutions for the benefit of passengers, he added.

# Certificates awarded to teachers after a five-day training at Chetna Training Center run by BLW Women Welfare Organization in BLW.

**Source/RSB-** At the Chetna Training Center operated by the Women Welfare Organization in BLW (Banaras Locomotive Works), a five-day training program on Childhood Testing, Assessment and Management was organized from 16 to 22 January 2026. Upon successful completion of the program, certificates were awarded to all participating teachers on 27 January 2026 by the Nai Subah organization. The President of the BLW Women Welfare Organization, Mrs. Monika Srivastava, presented appreciation certificates to all trainers. On this occasion, uniforms were distributed to all teachers and staff working at the Chetna Training Center, and sweets were distributed to the trainees. Thereafter, Mrs. Monika Srivastava also distributed uniforms to the teachers & staff of Bal Niketan School & the Crèche, and sweets to the children. Present on the occasion were Vice President of the Women Welfare Organization Mrs. Gauri Srivastava; Mrs. Gurmeet Kaur; Treasurer, Mrs. Shweta Srivastava; Secretary Mrs. Ritika Singh; Mrs. Shikha Jain; Mrs. Anju Gupta; Mrs. Rakhi Gupta; Mrs. Hansa; and Mrs. Anuja Khare.The objective of this training program was to provide teachers with an in-depth understanding of child development, acquaint them with advanced techniques related to assessment & management, and empower them to better understand the educational & mental needs of children.

# Integral Coach Factory Achieves Historic Milestone with the Rollout of its 80,000th Coach

**Source/RSB-** Integral Coach Factory (ICF), the world's largest coach-producing factory and the premier production unit of Indian Railways, has achieved a historic milestone by rolling out its 80,000th coach since its inception in 1955. Over the past seven decades, ICF has been a cornerstone of India's rolling stock programme, consistently setting benchmarks in design, technology, and production excellence.

The milestone coach, part of the prestigious Amrit Bharat Coach series, marks a significant achievement in ICF's journey of innovation and growth. ICF has also established a global footprint by exporting coaches to several countries across Asia and Africa.

From manufacturing conventional passenger coaches, ICF has evolved into a centre of excellence for advanced rolling stock, including EMU and DEMU trains, Air-Conditioned EMUs, High-Speed Accident Relief Trains, luxury tourist coaches such as the Maharaja's Express and Golden Chariot, Vistadome coaches, and metro coaches for Kolkata Metro.

Building on this legacy, ICF is spearheading the production of Vande Bharat trainsets and developing new variants such as Amrit Bharat Coaches, Namo Bharat Rapid Rail, and Vande Bharat sleeper trainsets.

The focus remains on enhancing passenger comfort, aesthetics, and quality while integrating cutting-edge technology. ICF has earned numerous accolades for its contributions to quality, environmental sustainability, and social responsibility.

On this occasion, Shri U. Subba Rao, General Manager/ICF, congratulated all employees since the inception, praising their dedication and stating that the milestone reflects ICF's enduring spirit of innovation and its vital role in shaping the future of Indian Railways.

# India's First LNG-Diesel Hybrid Rail Engine Rolled Out in Gujarat to Drive Green Mobility

**Source/RSB-**In a significant move to promote greener and more sustainable rail operations, Indian Railways has introduced the country's first LNG-Diesel dual-fuel DEMU train at Sabarmati in Ahmedabad. As part of the initiative, the driving power cars of the 1,400 HP DEMU have been modified to operate on a dual-fuel system, enabling the use of Liquefied Natural Gas (LNG) to substitute nearly 40 per cent of conventional diesel consumption.

Ahmedabad Divisional Railway Manager Ved Prakash informed that the retrofitted power cars have successfully completed field trials of more than 2,000 kilometres. The train is now running in regular passenger service without any operational issues.

He highlighted that the dual-fuel system is expected to deliver both environmental and economic advantages. The adoption of LNG will lead to a considerable reduction in carbon dioxide and nitrogen oxide emissions, contributing to improved air quality along railway corridors.

# RailOne App to be the Unified Platform for Passenger Services UTS-on-Mobile App to be Decommissioned from 1st March 2026

**Source/RSB-** The UTSonMobile App (UTS App) will be decommissioned with effect from 01.03. 2026. The decommissioning of the UTS App in a phased manner as detailed below:

In the initial phase, season ticket booking/renewal and new user registration were disabled on the UTS App. Subsequently, platform ticket booking and R-Wallet top-up functionalities have also been disabled, though the application continues to remain available on the App Store. It is further clarified that users who download or update the latest version of the UTS App will not be permitted to book platform tickets or recharge the R-Wallet through the UTS App.

**Important Clarification on R-Wallet Balance**

Railway passengers are hereby assured that the existing R-Wallet balance of users on the UTS App will remain completely safe and secure. The available R-Wallet balance will not lapse or be forfeited due to the decommissioning of the UTS App. The balance will be available for use on the RailOne App.

Passengers are advised to download and use the RailOne App, which will be the single, unified and official mobile platform for ticketing and passenger services. RailOne App offers Unreserved, Season and Platform ticketing, along with access to reserved ticketing services, through a single, user-friendly interface.

### Salient features of RailOne App

- *Passengers can book reserved tickets, unreserved tickets & platform tickets effortlessly from one app.*
- *The booking process is simple and secure, with multiple payment options including UPI, debit/credit cards, R-wallet and net banking.*
- *Live train running status, delays and updated arrival/departure timings, real-time coach position and platform information help passengers board trains with ease.*
- *Passengers can conveniently Track PNR status (Confirmed/RAC/Waitlisted). Manage cancellations and monitor refund status-all in one place.*
- *RailOne enables passengers to order food directly to their seats from IRCTC-approved vendors.*
- *Complaints, feedback & service requests can be lodged easily through integrated RailMadad support.*

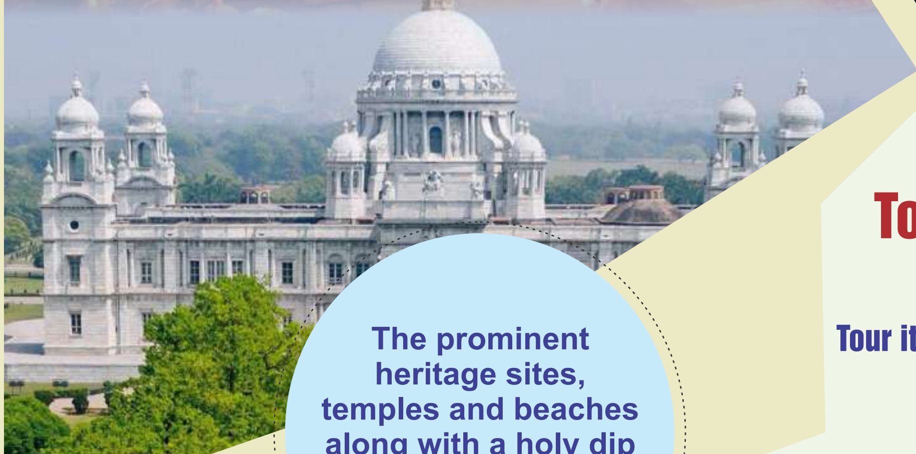

The prominent heritage sites, temples and beaches along with a holy dip at Gangasagar are the key attractions of this tour.

# IRCTC launches new Rail-Based Tourism Circuit for the Eastern part of India titled "Divine East Temple Tour".

## Tour itinerary covering Varanasi, Kolkata, Gangasagar, Puri, Bhubaneswar, Konark, Chilika and Baidyanath Dham (Jyotirlinga) in 10 days.

***Bharat Gaurav Deluxe Tourist Train will depart from Delhi Safdarjung Railway Station on March 09, 2026.***

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC), a Navratna Public Sector Enterprise under the Ministry of Railways, Government of India, has introduced a new tourism circuit titled "Divine East Temple Tour" on its Bharat Gaurav Deluxe Tourist Train. The thoughtfully curated 10-day rail-based journey offers devotees and travelers a unique opportunity to visit some of the most revered pilgrimage destinations along with culturally rich heritage sites across Uttar Pradesh, West Bengal, Odisha and Jharkhand.

The journey will begin from Delhi Safdarjung and would cover Varanasi, Kolkata, Gangasagar, Puri, Bhubaneswar, Konark, Chilika and Baidyanath Dham before returning back to Delhi. The significant sites that shall be toured are Kashi Vishwanath Temple (Jyotirlinga) and Ganga Aarti at Varanasi, followed by a visit to the cultural capital of India, Kolkata, covering landmarks such as Victoria Memorial and other city attractions and significant temples like Kali Ghat (Shakti Peeth) and Dakshineshwar Kali Mandir. Day Excursion of the sacred shores of Gangasagar, including a holy dip at the Sagar Sangam and darshan at Kapil Muni Temple is the main attraction of this tour. The journey continues to Puri, offering darshan at the revered Shri Jagannath Temple, along with a tour of the comprehensive Odisha circuit including Bhubaneswar, Dhauli Shanti Stupa, Udayagiri and Khandagiri Caves, the Konark Sun Temple (UNESCO World Heritage Site) and much more. The final spiritual destination of the tour is Baidyanath Dham (Deoghar), one of the twelve Jyotirlingas of Lord Shiva, before returning to Delhi Safdarjung on 18th March 2026, marking the conclusion of a memorable and spiritually enriching journey.

The all-inclusive tour offering of IRCTC is a perfect mélange of religious and leisure tourism and is aimed at providing passengers with a seamless, safe and enriching travel experience. The Bharat Gaurav Deluxe Tourist Train is equipped with modern amenities such as well-appointed cabins in AC III, AC II & AC I category, onboard restaurants serving hygienic vegetarian meals, enhanced safety and security features and dedicated tour managers. IRCTC has launched this special train tour at a price of Rs. 1,06,940/-per person for 1AC class, Rs. 98,925/- for 2AC and Rs. 79,285/- for 3 AC Class. Package Price covers train journey in AC classes, Accommodation in AC Hotels, all meals (VEG ONLY), all transfer & sight-seeing in AC Vehicles, Travel Insurance and services of IRCTC Tour Managers etc. Bookings for the Divine East Temple Tour are open on IRCTC's tourism portal and through authorized IRCTC tourism offices across the country.

**For further details, itinerary, and booking information, passengers may visit www.irctctourism.combharatgaurav or contact on Mobile no. 8287930299 (Prafulla), 8287930484 (Subhasree), 8287930032 (Abhishek), 8595931047 (Monika) and 8882826357 (Praneet).**